सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 128, नई दिल्ली । शुक्रवार, 19 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

घड़ी को सिर्फ देखा मत बल्कि वह करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो।

03 सिविल लाइन में डीडीए ने अक्रामक तरीके से गरीबों के घर तोड़े हैं

06 कवच-कुंडल की तलाश

08 प्रतिदिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं व आमजन की जनसुनवाई कर रहे है भीलवाड़ा सांसद

परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र नवम्बर माह में मोटर वाहन नियम/अधिनियम एवं सड़क सुरक्षा के प्रति

1. प्रदर्शनी,
2. संगोष्ठी,
3. विशेषज्ञ विचार एवम्
4. सड़क सुरक्षा पर आधारित पुस्तक लोकार्पण

समारोह आयोजित करने जा रहा है।

इस पत्रिका में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार एवम् उच्च न्यायालय (सभी राज्य भारत सरकार) द्वारा जनहित में जारी गैजेट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, आदेशों, दिशा निर्देशों को एक साथ उपलब्ध करवाएंगे और साथ ही यह विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे की किस राज्य के परिवहन विभाग द्वारा इनमें से क्या लागू है और क्या नहीं।

*जनहित और जन जागरूकता के प्रति समर्पित ट्रांसपोर्ट टुडे के इस विशेष अंक में जानकार, ज्ञानविध विशेषज्ञों से सहयोग प्रदान करने के लिए निवेदन करते हैं।

"आपके पास मोटर वाहन नियम अधिनियम और सड़क सुरक्षा से सम्बंधित जो जानकारी है उसे हमे जन जागरूकता के प्रति उपलब्ध करवाए"

हम पत्रिका में आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को आपके नाम से प्रस्तुत करेंगे।

जन जागरूकता में इस उद्देश्य को सफल बनवाने में सहयोग प्रदान करने वालो को योगदान के प्रति सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

आज भारत देश में हम सब का दायित्व बनता है की अगर सड़क सुरक्षा के प्रति हम सक्षम है, जानकार है तो अपनें ज्ञान के माध्यम से सड़क दुर्घटना जीरो कराने के प्रति जागरूकता फैलाने में सहयोग करे।

आशा करता हू हमारे द्वारा करे जाने वाले इस प्रयास में आप अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर राज्य परिवहन विभागो एवम्-अन्य विभागों द्वारा की जा रही कमियों को दूर करवाने और भारत देश में सड़क दुर्घटना के साथ सड़को पर होने वाली जान माल क्षति को रोकने के हिस्सेदार बनेंगे।

आप हमे अपने विचार, लेख, दस्तावेज़, फोटो, वीडियो

ईमेल
info@newsparivahan.com
news@newsparivahan.com
suggest@newsparivahan.com

और
व्हाट्सएप द्वारा
9811732095
9599232095
पर भेज सकते है।

संजय बाटला
संपादक, परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

नमो भारत के 25 स्टेशनों पर पार्किंग होगी खास, किस पर लगेगा शुल्क और मुफ्त में क्या मिलेंगी सुविधाएं; यहां जानें सबकुछ

एनसीआरटीसी का कहना है कि दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे सार्वजनिक परिवहन उपयोग की मौजूदा 37 प्रतिशत की हिस्सेदारी बढ़कर 63 प्रतिशत तक हो जाएगी। स्टेशनों पर तैयार किए जा रहे पार्किंग स्थलों में 1600 से अधिक चारपहिया और 6500 से अधिक दुपहिया वाहनों के खड़ा करने की सुविधा होगी।

नई दिल्ली। दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा लगातार प्रयास जारी है। इसी कड़ी में आरआरटीएस स्टेशनों पर बनाए जा रहे पार्किंग स्थलों पर आठ हजार से अधिक वाहनों को एक साथ खड़ा किया जा सकेगा। इन स्टेशनों को रणनीतिक रूप से पांच से 10 किमी की औसत दूरी पर विकसित किया जा रहा है।

एनसीआरटीसी का कहना है कि दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे सार्वजनिक परिवहन उपयोग की मौजूदा 37 प्रतिशत की हिस्सेदारी बढ़कर 63 प्रतिशत तक हो जाएगी। स्टेशनों पर तैयार किए जा रहे पार्किंग स्थलों में 1,600 से अधिक चारपहिया और 6,500 से अधिक दुपहिया वाहनों के खड़ा करने की सुविधा होगी।

मेरठ साउथ स्टेशन में बनी है सबसे बड़ी पार्किंग

दिल्ली से मेरठ तक पूरे आरआरटीएस कॉरिडोर पर 25 स्टेशन हैं। सबसे बड़ी पार्किंग मेरठ साउथ स्टेशन में बनाई जा चुकी है, जहां करीब 300 कारें और 900 दुपहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्किंग दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन पर विकसित की जा रही है, जहां करीब 275 कारें और 900 दुपहिया वाहन पार्क किए जा सकेंगे।

इस कॉरिडोर का 34 किलोमीटर का हिस्सा पहले से ही आठ आरआरटीएस स्टेशनों के साथ जनता के लिए संचालित है, जहां यात्रियों को पार्किंग की सुविधा दी गई है। इन पार्किंग स्थलों में ऑटो रिक्शा पार्क करने की सुविधा भी उपलब्ध है। स्टेशनों पर पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

ये रहेगा पार्किंग शुल्क

इन पार्किंग स्थलों पर सिर्फ पिक एंड ड्रॉप के लिए आने वाले वाहनों के लिए शुरुआती 10 मिनट तक कोई शुल्क नहीं होगा। 10 मिनट के बाद और छह घंटों तक साइकिल के लिए पांच रुपए, दुपहिया वाहनों के लिए 10 रुपए और चारपहिया वाहनों के लिए 25 रुपये चुकाने होंगे।

वहीं, छह से 12 घंटे के लिए साइकिल के लिए पांच रुपये, दुपहिया वाहनों के लिए 25 रुपये और चारपहिया वाहन के लिए 50 रुपये एवं 12 घंटे के बाद आरआरटीएस संचालन के घंटे समाप्त होने तक साइकिल के लिए 10 रुपये, दुपहिया वाहनों के लिए 30 रुपये और कारों के लिए 100 रुपये चुकाने होंगे। नन ऑपरेशनल घंटों के दौरान नाइट पार्किंग शुल्क साइकिल के लिए 20 रुपये, दुपहिया वाहनों के लिए 60 रुपये और कारों के लिए 200 रुपये तक होगा।

मिलेगी बैटरी स्वैपिंग की सुविधा

दिव्यांग यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए उनके वाहनों की पार्किंग के लिए अलग से जगह निर्धारित की गई है। स्टेशन में आसान प्रवेश के लिए रैंप भी बनाए गए हैं, ताकि वे नमो भारत ट्रेन में यात्रा की सुविधा का लाभ उठा सकें। एनसीआरटीसी अपने पार्किंग स्थलों पर नमो भारत के यात्रियों और लास्ट माइल सेवा प्रदाताओं, दोनों के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने की भी योजना बना रही है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

कांवड़ यात्रा यात्रा को देखते 300 बसों का होगा डायवर्जन

अंतिम रूट मैप तैयार; 50 हजार यात्रियों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

गाजियाबाद सहित कई जिलों में 22 जुलाई की आधी रात से भारी वाहनों का रूट डायवर्जन शुरू हो जाएगा। इन भारी वाहनों में बसें भी शामिल हैं। परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों के लिए अंतिम रूट मैप तैयार कर लिया है। अब इसका असर 50 हजार यात्रियों पर सीधा पड़ेगा। इतना ही नहीं इन यात्रियों को किराया भी ज्यादा देना होगा।

परिवहन विशेष न्यूज

साहिबाबाद। गाजियाबाद समेत अन्य विभिन्न जिलों में 22 जुलाई रात 12 बजे के बाद भारी वाहनों का डायवर्जन शुरू हो जाएगा। परिवहन निगम ने रोडवेज बसों के डायवर्जन के लिए अंतिम रूट मैप तैयार कर लिया है।

रूट में बदलाव होने से रोजाना करीब 50 हजार यात्रियों पर अतिरिक्त किराए का भार पड़ेगा। वहीं, वर्तमान रूटों के बीच में पड़ने वाले शहर के यात्रियों को रोडवेज बस सेवा का लाभ नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

डायवर्जन शुरू होने पर कौशांबी डिपो से गढ़मुक्तेश्वर, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, धामपुर व कालागढ़ के लिए संचालित बसों का रूट बदलेगा। वहीं, गाजियाबाद डिपो से बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़ व मेरठ के लिए संचालित बसों का रूट बदलेगा।

इन शहरों के लिए संचालित 300 से अधिक बसों के रूट बदलने से किलोमीटर भी बढ़ जाएगा। साधारण बस की एक किलोमीटर दूरी बढ़ने पर 1.30 रुपये के हिसाब किराए में वृद्धि कर दी जाएगी। इसी तरह एसी बसों का किराया भी प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा।

अकेले कौशांबी डिपो से बरेली मार्ग पर पांच रीजन की करीब 100 बसों से रोजाना 20 हजार यात्री सफर करते हैं। इसी तरह धामपुर व कालागढ़ के लिए करीब छह से सात हजार यात्री रोजाना सफर करते हैं।

यानी कुल मिलाकर रोजाना 50 हजार से अधिक यात्रियों को अतिरिक्त किराया चुकाना होगा। अधिकारियों का मानना है कि लंबे रूट की बसों में 50 से 100 रुपये तक किराए की वृद्धि हो सकती है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकिट मशीन (ईटीएम) को अपडेट कराया जाएगा।

लालकुआं पर बनेगा अस्थाई बस अड्डा

डायवर्जन शुरू होने के साथ ही बसों को शहर में अंदर जाने पर पाबंदी लग जाएगा। अलीगढ़ समेत विभिन्न शहरों की बसों के संचालन के लिए लालकुआं पर अस्थाई बस अड्डा बनाया जाएगा। यहीं से इन बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए लालकुआं का सर्वे कर लिया गया है।

मोहननगर होते हुए जाने वालीं बसों का संचालन यूपीगेट, एनएच-नौ से होगा:

मोहननगर से भारी वाहनों का डायवर्जन रहेगा। जिन शहरों की बसों का संचालन मोहननगर से किया जाता है उन बसों का संचालन यूपी गेट होते हुए एनएच-नौ से किया जाएगा।

कौशांबी डिपो से बरेली का रूट

वर्तमान रूट : कौशांबी-संभल-मुरादाबाद-रामपुर-बरेली

डायवर्जन : कौशांबी-बुलंदशहर-अनूपशहर-संभल-मुरादाबाद-बरेली

मुरादाबाद में डायवर्जन होने के बाद : कौशांबी-बुलंदशहर-अनूपशहर-संभल-बिलारी-शाहबाद-रामपुर-बरेली

कौशांबी डिपो से कालागढ़ का रूट

वर्तमान रूट: कौशांबी-धामपुर-कालागढ़

डायवर्जन होने पर : कौशांबी-किठौर-बिजनौर-चांदपुर-नूरपुर-धामपुर-अफजलगढ़-कालागढ़

कौशांबी डिपो से गढ़मुक्तेशवर का रूट:

वर्तमान रूट : कौशांबी-हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर

डायवर्जन : कौशांबी-बुलंदशहर-स्याना-गढ़मुक्तेश्वर

गाजियाबाद डिपो से मेरठ का रूट

वर्तमान रूट : गाजियाबाद-मोहननगर-मोदीनगर-मेरठ

डायवर्जन : गाजियाबाद-दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे-मेरठ

गाजियाबाद डिपो से अलीगढ़ का रूट

वर्तमान रूट : गाजियाबाद-बुलंदशहर-खुर्जा-अलीगढ़

डायवर्जन : लालकुआं-यूपी गेट-लालकुआं-बुलंदशहर-अलीगढ़

बसों के लिए नया रूट मैप तैयार कर लिया गया है। ज्यादातर शहरों के किराए में वृद्धि होगी। यात्रियों को परेशानी न हो इसका प्राथमिकता के साथ ध्यान रखा जाएगा।

-शिव बालक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, कौशांबी डिपो।

मयूरभंज जिले के बादामपहाड़ से क्योंझर नई रेलवे लाइन होगी

मनोरंजन सासमल, स्टेटे हेड उडीशा

भुबनेश्वर : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देशानुसार, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन प्रशासन ने मंगलवार को मयूरभंज जिले में तीन नई रेल-लाइन कनेक्शन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं और इसकी अंतिम तिथि 8 अगस्त है।यह जानकारी उपलब्ध कराये जाने के बाद जिले की आम जनता महामहिम द्रौपदी मुर्मू एवं केंद्र सरकार के साथ-साथ रेल मंत्री एवं सभी रेल अधिकारियों सहित दक्षिण पूर्व रेलवे महाप्रबंध/डीआरएम चक्रधरपुर को हृदय से धन्यवाद देना चाहती है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि मयूरभंज जिले में तीन रेलवे परियोजनाएं मयूरभंज जिले के बादामपहाड़ से क्योंझर नई रेलवे लाइन को जोड़ने, गोरोमाहिसानी से बंगरीपोशी तक नई रेलवे लाइन और बंगरीपोशी से चाकुलजे तक नई रेलवे कनेक्टिंग परियोजना को जोड़ने वाली हैं।

अब मेट्रो में शराब की दो बोतल लेकर एनसीआर नहीं जा पाएंगे यात्री, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई; डीएमआरसी ने किया स्पष्ट

आबकारी नियम के अनुसार दिल्ली से दूसरे राज्य में सील बंद दो बोतल शराब लेकर जाने की स्वीकृति नहीं है। एक बोतल सील बंद शराब लेकर दूसरे राज्य में जाया जा सकता है। दिल्ली मेट्रो का परिचालन एनसीआर में उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद और हरियाणा के गुरुग्राम फरीदाबाद बल्लभगढ़ व बहादुरगढ़ तक होता है। वहीं संबंधित राज्य का जो भी आबकारी नियम है वह लागू होंगे।

नईदिल्ली। दिल्ली से मेट्रो में सील बंद दो बोतल शराब लेकर एनसीआर में जाना आबकारी नियम का उल्लघंन होगा और पकड़े जाने पर कार्रवाई भी सकती है। मेट्रो में सील बंद शराब लेकर चलने के मामले पर संबंधित राज्य का आबकारी नियम लागू होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने यह बात स्पष्ट की है। उल्लेखनीय है कि पहले सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो में सील बंद शराब लेकर सफर करने की स्वीकृति दी। पिछले वर्ष जून में डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के सभी कॉरिडोर की मेट्रो ट्रेनों में सील बंद दो बोतल शराब लेकर जाने का प्रावधान किया था। बाद में दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया था और आबकारी नियम का उल्लघंन बताया था।

डीएमआरसी ने नियम में सुधार का दिया निर्देश : दिल्ली के आबकारी विभाग ने डीएमआरसी को बाकायदा अपने नियम में सुधार करने का निर्देश दिया था। आबकारी नियम के अनुसार दिल्ली से दूसरे राज्य में सील बंद दो बोतल शराब लेकर जाने की स्वीकृति नहीं है। एक बोतल सील बंद शराब लेकर दूसरे राज्य में जाया जा सकता है। दिल्ली मेट्रो का परिचालन एनसीआर में उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ व बहादुरगढ़ तक होता है। डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (जनसंपर्क) अनुज दयाल ने कहा कि हम एक या दो बोतल की बात नहीं कर रहे, दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी के अलावा उत्तर प्रदेश व हरियाणा के शहरों में भी सेवाएं दे रही है। इसलिए संबंधित राज्य का जो भी आबकारी नियम है वह लागू होंगे।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ट्रक मालिको के हित मे प्रदर्शन और मांग की झलकियां

डेंगू के लक्षणों की अनदेखी बन सकती है मौत का कारण, डॉक्टर ने बताए इसके रिस्क फैक्टर्स और बचाव के तरीके

मानसून आते ही Dengue ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देश के कई हिस्सों में इस बीमारी के मामले सामने आ रहे हैं। यह मच्छरों से होने वाली एक बीमारी है जो मुख्य रूप में एडीज मच्छर के काटने से होती है। अगर समय रहते इसका निदान कर लिया जाए तो इससे बचना मुमकिन है वरना यह बीमारी मौत समेत कई गंभीर हालातों की वजह बन सकती हैं।

नई दिल्ली। देश के अलग-अलग हिस्सों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बरसात के दिनों में मच्छरों से होने वाली बीमारियां काफी आम होती हैं। इसी क्रम में जहां इन दिनों महाराष्ट्र में जीका वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं देश के अन्य हिस्सों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यह मच्छरों से होने वाली एक गंभीर बीमारी है, जिसका इन दिनों कई लोग शिकार हो रहे हैं। साल के इस समय हर बार इसके मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है।

ऐसा इसलिए क्योंकि बरसात के दिनों अक्सर बारिश का पानी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से मच्छरों के पनपने के लिए बढ़िया जगह मिल जाती है। ऐसे में जरूरी है कि इस बीमारी से बचने के लिए सभी जरूरी जानकारी का पता हो। यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है, अगर समय रहते इसका निदान और इलाज न किया जाए। ऐसे में आज इस आर्टिकल में न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स लैब, नोएडा के प्रमुख डॉ.विज्ञान मिश्र से जानेंगे डेंगू के कुछ रिस्क फैक्टर और इससे निपटने के तरीकों के बारे में-

क्या है डेंगू बुखार?

डॉक्टर बताते हैं कि डेंगू बुखार, एक मच्छर जनित यानी मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है, जो स्वास्थ्य से जुड़े कई जोखिम पैदा करता है। हालांकि, आमतौर पर इसके असामान्य लक्षणों की वजह से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह लापरवाही कई गंभीर खतरे को न्यौता देती है।

डेंगू के लक्षण

रैश

सिरदर्द

तेज बुखार

जोड़ों में दर्द

आंखों से पीछे दर्द

मतली और उल्टी

डेंगू के रिस्क फैक्टर

डेंगू के रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हुए डॉक्टर ने बताया कि डेंगू के लक्षणों को नजरअंदाज करने से यह सीवियर डेंगू में बदल सकता है। इसके अन्य रिस्क फैक्टर्स में हेमरेज, ऑर्गन फेलियर और यहां तक कि मौत जैसी जटिलताएं भी शामिल हो सकती हैं।

ऐसे करें बचाव

डेंगू से बचाव के लिए डॉक्टर ने कुछ कारगर तरीके भी बताए, जिनमें निम्न उपाय शामिल हैं-

कंटेनरों, नालियों और खराब टायर में पानी जमा न होने दें। अगर इनमें पानी भरा है, तो इसे तुरंत खाली कर दें।

मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें और सुरक्षात्मक कपड़े पहनें, खासकर सुबह और शाम के समय।

शाम होते ही घर की खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर दें।

इंसेक्टिसाइड्स का नियमित छिड़काव और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना भी इससे बचने का कारगर तरीका है।

वेट लॉस की कोशिश में लगे लोगों के लिए खुशखबरी!
भारत में जल्द लॉन्च होगी वजन घटाने वाली दवा

इन दिनों मोटापा एक गंभीर समस्या बन चुका है और दुनियाभर में कई लोग इससे प्रभावित है। यह कई स्वास्थ्य समस्याओं की वजह भी बन सकता है जिसकी वजह से कई लोग अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी वजन कम नहीं होता है। ऐसे में जल्द ही भारतीय बाजार में Weight Loss ड्रग लॉन्च होने वाला है।

नईदिल्ली। मोटापा एक गंभीर समस्या है, जिससे दुनियाभर में कई लोग प्रभावित है। इन दिनों कई लोग इनएक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वजन का बढ़ना एक आम समस्या बन गई है। मोटापा कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकता है और इस बारे में खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी चेतावनी जारी कर चुका है। ऐसे में खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए कई लोग वेट कंट्रोल करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। हालांकि, कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी वजन ठस का मस नहीं होता, जिसकी वजह से सारी मेहनत पानी में चली जाती है। ऐसे में अब वेट लॉस (Weight Loss) की कोशिश में लगे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है।

अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में चर्चित ओजेम्पिक, जेपबाउंड जैसी वजन घटाने वाली दवाएं अब जल्द ही भारतीय बाजारों में दस्तक देने वाली है। इस सिलसिले में भारतीय ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग स्टेंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) ने फार्मास्यूटिकल कंपनी 'ऐली लिली' के टिरजेपेटाइड (Tirzepatide) नामक वेट लॉस ड्रग को हरी झंडी दे दी है। यह एक्टिव इंग्रीडिएंट Eli Lilly की मशहूर दवाओं Mounjaro जो डायबिटीज के लिए है और Zepbound जो वजन घटाने के लिए है, में भी मौजूद होता है। पिछले साल अमेरिका के FDA ने वयस्कों में वजन बढ़ने की समस्या के लिए जेपबाउंड को मंजूरी दी थी।

भारतीय ड्रग रेगुलेटर की इस मंजूरी के बाद अब जल्द ही इस दवा की मेन्युफैक्चरर एली लिली भारतीय बाजार में अपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगी। हालांकि, अभी इस दवाई के आयात और इसकी मार्केटिंग को डायबिटीज के लिए मंजूरी दी गई है, नकि वजन घटाने के लिए। CDSCO अभी मोटापे से इसके कनेक्शन की समीक्षा कर रहा है। लेकिन क्या टिरजेपेटाइड सच में वजन कम करने में कारगर है, अगर हां, तो यह कैसे काम करता है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज इस आर्टिकल में।

टिरजेपेटाइड क्या है?

टिरजेपेटाइड एली लिली की दवाओं, मौन्जारो और जेपबाउंड का एक्टिव इंग्रीडिएंट है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि टिरजेपेटाइड शरीर में दो जरूरी हार्मोन्स- जीआईपी और जीएलपी-1 की तरह काम करता है।

कैसे वजन कम करता है टिरजेपेटाइड?

जब इसे इंजेक्ट किया जाता है, तो यह इन हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स एक्टिव करता है, जिसके कई प्रभाव होते हैं। यह पैनक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए स्टीमूलेट करता है और ब्रेन को पेट भरा हुआ महसूस करने का संकेत भी देता है। इस तरह यह दवाई न सिर्फ ब्लड में शुगर के लेवल को कम करती है, बल्कि भूख भी कम करती है, जिससे मोटापे से पीड़ित लोग ज्यादा खाने से बचे रहते हैं।

वहीं, कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि टिरजेपेटाइड और भी ज्यादा प्रभावी इसलिए है, क्योंकि यह जीआईपी की नकल करता है, जो भूख को कम करने के साथ-साथ शरीर में शुगर और फैट को तोड़ने के तरीके में सुधार कर सकता है, जिससे वेट लॉस की प्रक्रिया में मदद मिलती है।

अध्ययनों में भी हुआ साबित

कुछ अध्ययनों से भी पता चलता है कि वजन घटाने के लिए टिरजेपेटाइड बहुत प्रभावी होता है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में जुलाई 2022 में पब्लिश हुए एक अध्ययन में पता चला कि टिरजेपेटाइड की कम डोज लेने वाले लोगों ने लगभग एक साल में लगभग 16 किलोग्राम वजन कम किया। वहीं, इसकी ज्यादा खुराक लेने वालों के वजन में 22 किलोग्राम की कमी आई।

क्या टिरजेपेटाइड के कोई साइड इफेक्ट्स हैं?

बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो एक अध्ययन से यह पता चलता है कि टिरजेपेटाइड से कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं हो सकती है। इसकी हाई डोज लेने वाले लगभग एक-तिहाई लोगों को मतली का अनुभव हुआ और पांच में से एक को दस्त का अनुभव हुआ। इसके अलावा इस दवा को लेने वाले कुछ लोगों ने पेट दर्द, उल्टी, कब्ज, सिरदर्द और चक्कर आने की भी शिकायत की।

इसके अलावा एफडीए के अनुसार, जेपबाउंड लेने वाले लोगों को डकार आना, बाल झड़ना और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज का भी अनुभव हो सकता है। साथ ही किसी प्रेग्नेंट महिला को यह दवा लेने से परहेज करना चाहिए। साथ ही एफडीए का यह भी कहना है कि इस दवा को लेने वाले लोगों में डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स पर नजर रखी जानी चाहिए और इसके लक्षण नजर आने पर इस दवा को तुरंत बंद कर देना चाहिए।

कब तक भारतीय बाजार में आएगी दवा?

एली लिली के सीईओ डेविड रिक्स ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया था कि मौन्जारो 2025 की शुरुआत में भारत में लॉन्च हो सकती है। वहीं, नोवो नॉर्डिस्क 2026 तक भारत में अपनी वजन घटाने वाली दवा लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस दवा की भारत में डिमांड बढ़ने की काफी संभावना है, क्योंकि यहां टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे वाले लोगों की संख्या दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

नागरिक भावना जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है और देश की प्रतिष्ठा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है

विजय गर्ग

नागरिक भावना की कमी के कारण कई सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन इसे जागरूकता और कड़े दंडात्मक उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से पैदा किया जा सकता है। नागरिक उन चार आवश्यक तत्वों में से एक हैं जो किसी देश को परिभाषित करते हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक निस्संदेह किसी भी राष्ट्र के लिए एक संपत्ति है। आज, हमारा देश अत्याधुनिक सुविधाओं का दावा करता है, जिसमें बुनियादी ढांचे, सेवाओं, रसद और सार्वजनिक परिवहन को उन्नत करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, समावेशी और एकीकृत नीतियां बनाई जा रही हैं और व्यापक नागरिक-केंद्रित कार्यान्वित किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन नागरिकों को सार्वजनिक वस्तुओं को बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाने और यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि संसाधन सभी के लिए, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए सुलभ हों। नागरिक भावना समाज में दूसरों के बारे में विचार करने और सार्वजनिक वस्तुओं के प्रति जिम्मेदारी की भावना रखने का कार्य है। इसे ₹धारणाओं और दृष्टिकोणों का एक समूह के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो किसी समूह के भीतर किसी व्यक्ति के स्वतंत्र कार्यों या कार्यों को कई लोगों के लाभ के लिए निर्देशित करता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है।₹ इसके विपरीत, नागरिक भावना की कमी साथी प्राणियों के प्रति उपेक्षा का प्रतीक है, जो दूसरों को उनके अधिकार तक पहुँचने के उचित अवसर से वंचित करती है। नागरिक भावना में सामाजिक और नैतिक रूप से अच्छा व्यवहार, आचरण और दृष्टिकोण शामिल है। भारतीयों में देशभक्ति की जड़ें गहरी हैं और हमारी सभ्यता के मूल्यों और लोकाचार के प्रति हमारा गहरा लगाव है। हालाँकि, हममें से बहुत से लोग इसमें निपुण नहीं हैं, और नागरिक नियमों का अक्सर किसी न किसी तरह से उल्लंघन किया जाता है। नागरिक भावना की कमी के उदाहरणों में बर्बरता, सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग, कानूनों की अवज्ञा, यातायात नियमों का उल्लंघन, कर चोरी, पूर्वाग्रह, असहिष्णुता, अनुशासनहीनता, सांप्रदायिकता और अन्य सामाजिक और धार्मिक समूहों की मान्यताओं और प्रथाओं के प्रति असंवेदनशीलता शामिल हैं। ये व्यवहार कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा करते हैं और सामाजिक मानदंडों और उचित व्यवहार की उपेक्षा में निहित हैं। पिछले कुछ दशकों में हमारे देश में साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद, लोग अक्सर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह बने रहते हैं। इसके उदाहरणों में घरेलू कचरे को सड़कों पर फेंकना शामिल है; सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना इत्यादि। इस तरह का असभ्य व्यवहार बड़े पैमाने पर और चिंताजनक है, जो समाज के सामूहिक कल्याण पर हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। यह न केवल सामाजिक संघर्षों में बदल जाता है, बल्कि एक दुष्चक्र को भी जन्म देता है, जहां इस तरह का व्यवहार, जो अक्सर एक आसान तरीका होता है, कई लोगों द्वारा तुरंत अनुकरण किया जाता है, जिससे समस्या का समाधान करना मुश्किल हो जाता है। भारत में 2022 में 461,312 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 168,491 लोगों की दुखद हानि हुई। इनमें से कई दुर्घटनाओं को टाला जा सकता था यदि लोग यातायात नियमों का उल्लंघन न करते। इसी प्रकार, मिलावट, भ्रष्टाचार और शोषण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को एक सचेत दृष्टिकोण के माध्यम से कम किया जा सकता है जो स्व-हित पर सामान्य हित को प्राथमिकता देता है। नागरिक भावना जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है और देश की प्रतिष्ठा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नागरिक गुणों को विकसित करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि बारहमासी और नई दोनों समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है। शिक्षा लोगों को सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन तथ्य यह है कि महानगरों में रहने वाले सुशिक्षित व्यक्ति भी अक्सर अनियंत्रित और असभ्य व्यवहार करते हैं।यह आवश्यक है कि रचनात्मक और सकारात्मक भूमिकाएँ निभाने की इच्छा "अंदर से" आनी चाहिए। बड़ों को युवाओं के अनुकरण के लिए अच्छे उदाहरण स्थापित करने की ज़रूरत है। जागरूकता फैलाना, अच्छी प्रथाओं को पुरस्कृत करना और कानून के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई लागू करना लोगों में नागरिक भावना पैदा करने के लिए प्रभावी रणनीति हो सकती है।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

गुरु - पूर्णिमा, 21 जुलाई 2024, रविवार

आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। साधारण भाषा में गुरु वह व्यक्ति हैं जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पूरे भारत में यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 21 जुलाई 2024 रविवार को मनाया जाएगा।

गुरु पूर्णिमा महत्व-:

पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद्भागवत और अट्ठारह पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था, और उनका जन्मोत्सव गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।

गुरु पूर्णिमा मुहूर्त-:

21 जुलाई 2024 रविवार का संपूर्ण दिन गुरु पूजन का दिन रहेगा।

गुरु पूजन-:

1. इस दिन प्रातःकाल स्नान पूजा आदि नित्यकर्मों को करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए।
2. उसके उपरांत अपने प्रथम गुरु माता- पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए।
3. भगवान श्री हरि विष्णु व भगवान श्री व्यास जी को सुगंधित फल- फूल इत्यादि अर्पित करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए।
4. उपरांत यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो अपने गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊँचे सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए।
5. इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर कुछ दक्षिणा यथासामर्थ्य धन के रूप में भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
6. जहां से भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है जो हमारे ज्ञान को पुष्ट करता है, चाहे फिर वो कोई व्यक्ति हो या कोई पदार्थ या कोई अच्छा ग्रंथ, उसका हृदय से आभार मानना चाहिए।
7. इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु जहां से भी आपने कुछ अच्छा सीखा है, जहां से भी अच्छे मार्गदर्शन व श्रेष्ठ संस्कार मिलते हैं वह सभी गुरु की श्रेणी में आते हैं। अतः उन सब का भी धन्यवाद करना चाहिए।
8. गुरु की कृपा व्यक्ति के हृदय का अज्ञान व अन्धकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की सम्पूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है अतः गुरु के प्रति हमेशा श्रद्धा व समर्पण भाव रखने चाहिए।
9. गुरु से मन्त्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ है, और गुरु का आभार व्यक्त करने के लिए भी इस दिन का विशेष महत्व है। अतः इस पर्व को श्रद्धापूर्वक जरूर मनाना चाहिए।

"BIO-CLOCK"

अगर हमें सुबह जल्दी बाहर जाना है या कुछ काम है, तो हम सुबह 4.00 बजे का अलार्म लगाकर सो जाते हैं.

और अक्सर हम उस दिन Alarm के पहले ही उठ जाते हैं...

"This is Bio-clock".

बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो 80-90 की उम्र में चले जाएँगे.

और काफी लोग ये विश्वास करते हुए अपनी Bio-clock दिमाग़ में set कर लेते हैं, कि 50-60 की उम्र में सभी बीमारियाँ उन्हें घेर लेंगी, ऐसे लोग सामान्यतः 50-60 की उम्र में बीमारियों से घिर जाते हैं और जल्दी ही भगवान को प्यारे भी हो जाते हैं।

असल में हम अंजाने में अपनी गलत Bio-clock सेट कर लेते हैं।

जापान में लोग आराम से सौ साल तक जीते हैं, क्योंकि उनकी Bio-clock उसी तरह सेट रहती है।

अतः मित्रों,

हम लोग अपनी Bio-clock इस तरह सेट करें, जिससे हम कम से कम सौ साल तक जी सकें।

याद रखिए "Age is just a Number game",

but,

"Old Age" is a "mindset".

कुछ लोग 75 साल की उम्र में अपने आप को young महसूस करते हैं, तो कुछ लोग 50 की उम्र में भी खुद को बूढ़ा महसूस करते हैं।।

हमें अपने भीतर ये विश्वास बनाना है कि हम 40 से 60 वर्ष की उम्र में उन सभी बीमारियों से दूर हो चुकेंगे, जो पहले भी कभी हुई हों,

ताकि हमारी bio-clock वैसे ही set हो जाए.

Then, there is no chance of getting any disease.

Look young.

अपनी वेशभूषा, और look सदैव ऐसा रखें ताकि young नज़र आएँ।

Do not allow the appearance of ageing.

Be active.

अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार वॉकिंग, जॉगिंग कीजिए, और अपने आप को किसी अच्छे काम में व्यस्त रखिये।।

यह विश्वास बनाइए कि उम्र के साथ हेल्थ बेहतर होगी. (It's true).

NEVER, EVER ALLOW THE BIO-CLOCK SET YOUR ENDING....

कभी भी Bio-Clock को आपके जल्दी स्वर्ग सिधारने की अनुमति मत दीजिए।

लाइफ़ में एन्जॉय कीजिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। लेकिन एंजॉय करने के तरीके पवित्र व सादगी भरे होने चाहिए।

प्रकृति के साथ अपना तालमेल ज्यादा से ज्यादा बठाइए। क्योंकि जो प्रकृति के जितना ज्यादा नजदीक होता है उतना ही स्वस्थ व सुखी रहता है।

ध्यान रखें, हम जैसा अपने मन में सोचते हैं, हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाएँ उसी हिसाब से काम करती हैं। अतः जीवन में हमारी सोच, हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए।।

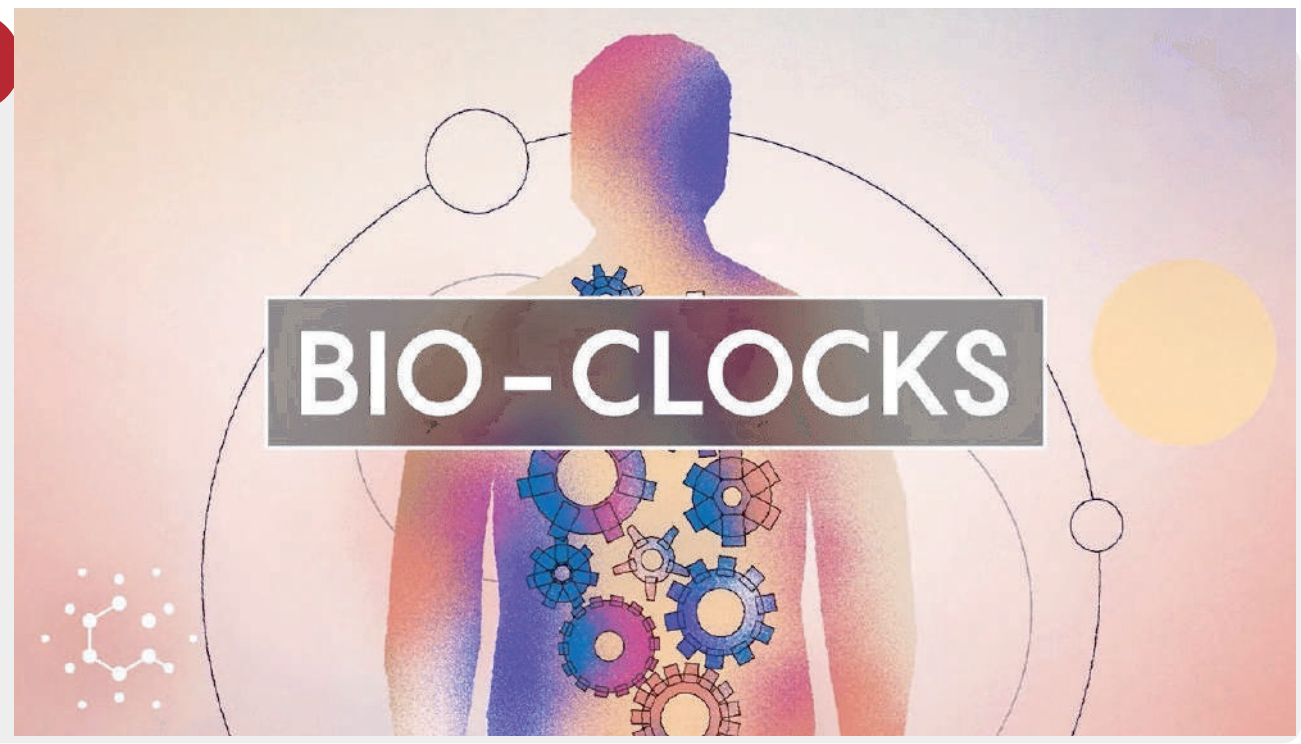

डीयू विभागों व कॉलेजों में एससी/एसटी , ओबीसी अभ्यर्थियों को किया जा रहा है नॉट फाउंड सूटेबल

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध विभागों व कॉलेजों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है । बता दें कि विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर , एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर की नियुक्तियों की प्रक्रिया पिछले दो साल से चल रही है । अभी तक 4600 पदों को भरा जा चुका है । दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों व संबद्ध कॉलेजों में अनुसूचित जाति (एससी) अनुसूचित जनजाति (एसटी) व ओबीसी के अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्तियों में नॉट फाउंड सूटेबल किया जा रहा है । नॉट फाउंड सूटेबल किए जाने को लेकर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों में गहरा रोष व्याप्त है । उनका कहना है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही क्यों नॉट फाउंड सूटेबल किया जाता है ? वाणिज्य विभाग , शिक्षा विभाग , फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज , (एफएमएस) राजनीति विज्ञान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एमआईएल के बंगाली विभाग के अलावा कॉलेज स्तर पर भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को एनएफएस किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है । जल्द ही फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस संसदीय समिति , नेशनल एससी,एसटी कमीशन , नेशनल ओबीसी कमीशन व सांसदों से मिलकर नॉट फाउंड सूटेबल संबंधी ज्ञापन देगा और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के विषय में बताएगा ।

फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के चेयरमैन डॉ हंसराज सुमन ने बताया है कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टरडीज (एफएमएस) , राजनीति विज्ञान विभाग , शिक्षा विभाग (सीआईई) डिपार्टमेंट ऑफ एमआईएल के बंगाली विभाग व वाणिज्य विभागों में एससी /एसटी ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कोटे के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल किया गया। उन्होंने यह भी बताया है कि बहुत से विभाग एससी /एसटी , ओबीसी कोटे के अभ्यर्थियों की मेरिट वेटिंग लिस्ट भी नहीं बनाते । कुछ शिक्षकों के छोड़कर जाने के बाद उस मेरिट लिस्ट से पदों को भर लिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ?

डॉ. सुमन ने बताया है कि इससे पहले भी फैकेल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टरडीज (एफएमएस) में सहायक प्रोफेसर के 29 पद विज्ञापित किए गए जिसमें 6 पदों पर नॉट फाउंड सूटेबल किया गया । इनमें ओबीसी--04 , एससी --01 , एसटी --01 है । इसी तरह से पिछले दिनों राजनीति विज्ञान विभाग में भी ओबीसी --02 पदों पर नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया गया ।

वाणिज्य विभाग में भी ईडब्ल्यूएस कोटे के --02 उम्मीदवारों को भी नॉट फाउंड सूटेबल किया गया । इसी विभाग में पिछले दिनों प्रोफेसर पद पर हुए साक्षात्कार में एससी -01 अभ्यर्थी को नॉट फाउंड सूटेबल किया गया । उन्होंने बताया है शिक्षा विभाग (सीआईई) में 5 पदों पर नॉट फाउंड सूटेबल किया गया । इसमें एससी --1 प्रोफेसर , एसटी --1 एसोसिएट प्रोफेसर , ओबीसी --1 एसोसिएट प्रोफेसर व ओबीसी --2 प्रोफेसर को नॉट फाउंड सूटेबल किया गया । इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ एमआईएल , बंगाली विभाग में एससी--1 पद पर नॉट फाउंड सूटेबल किया गया ।

डॉ. सुमन ने बताया है कि विभागों की तरह कॉलेजों ने भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल किया है । दौलतराम कॉलेज में रसायन विज्ञान विभाग में एससी --1 सहायक प्रोफेसर पद पर नॉट फाउंड सूटेबल किया । डीएवी कॉलेज सांध्य के वरिष्ठ शिक्षक प्रो.बासुकी चौधरी ने बताया है कि उनके यहाँ भी इतिहास विभाग व राजनीति विभाग में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल किया गया । लेडी श्रीराम कॉलेज के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर ओबीसी --1 पद पर नॉट फाउंड सूटेबल किया है । इसी तरह श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ईडब्ल्यूएस पोस्ट पर नॉट फाउंड सूटेबल किया । हाल ही में कमला नेहरू कॉलेज के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में ओबीसी --1 पद पर नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया गया । इससे पहले हंसराज कॉलेज के हिन्दी विभाग में भी अनुसूचित जनजाति (एसटी) के --01 उम्मीदवार को नॉट फाउंड सूटेबल किया गया । हालांकि कॉलेज द्वारा इसे फिर से विज्ञापित किया गया है । डॉ. सुमन का कहना है कि अभी 80 फीसदी नियुक्ति हुई है और यदि इसी तरह से आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाता रहेगा तो दूसरे विभाग व कॉलेज भी इस नीति को अपना लेंगे इसलिए इसे रोका जाना बहुत जरूरी है ।

डॉ.सुमन ने कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को लिखें पत्र में लिखा है कि जिन विभागों में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल किया गया है उनकी जांच कराने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी गठित की जाए । कमेटी में दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर से सेवानिवृत्त प्रोफेसर ,यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय , संसदीय समिति , एससी, एसटी कमीशन , ओबीसी कमीशन से एक-एक सदस्य के अलावा डीओपीटी/लायजन ऑफिसर हो । यह कमेटी यह भी जांच करे कि इन पदों पर कितने उम्मीदवार साक्षात्कार के समय उपस्थित हुए, कितने अनुपस्थित, चयन समिति की मिनट्स में किस आधार पर इन अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल किया गया है । साथ ही आरक्षित श्रेणी के ऑब्जर्वर ने अपना विरोध दर्ज मिनट्स में कराया है या नहीं ? इसकी जांच के बाद कमेटी सम्पूर्ण जानकारी मीडिया को दे ताकि पता चल सके कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही नॉट फाउंड सूटेबल क्यों किया जाता है ?

नीट पेपर रिज़ल्ट: सुप्रीम कोर्ट ने दी शनिवार की डेडलाइन, 22 जुलाई को फिर होगी सुनवाई

परिवहन विशेष।एसडीसेठी। नीट पेपर विवाद मामले पर सुप्रीमकोर्ट ने बडा आदेश दे डाला। सुप्रीमकोर्ट ने सरकार को शहर और सेंटर वाइज सभी छात्रो का शनिवार 20 जुलाई तक ऑनलाइन रिजल्ट डालने का आदेश दे दिया है। सुप्रीमकोर्ट की सुनवाई आज गुरूवार को सीबीआई रिपोर्ट से शुरूआत हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओ के कम से कम नंबर IIT मद्रास की रिपोर्ट, पेपर में गडबडी कब और कैसे हुई ?कितने, सॉलवर्स पकडे गए ?,दोबारा जांच की मांग और पेपर में गडबडी की पूरी टाइमलाइन पर चर्चा हुई। कोर्ट ने एनटीए को सभी छात्रो के सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहा है।साथ ही काउंसलसिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने सभी छात्रो के परिणाम-शहरवार और केंद्रवार शनिवार 20 जुलाई दोपहर 12:00 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किए जाने चाहिए। कोर्ट ने 22 जुलाई तक काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया । एसजी ने कहा कि काउंसिलिंग में कुछ लगेगा। यह 24

जुलाई के आस-पास शुरू होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड ने कहा कि हम सोमवार को ही सुनवाई करेगे।अब नीट विवाद में सोमवार को होने वाली सुनवाई का इंतजार करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि 22-23 लाख में से कितने छात्रो ने अपना एग्जाम सेंटर बदला? इस पर एनटीए ने जवाब दिया कि करेक्शन विंडो के नाम पर छात्रो ने सैंटर बदला है।15000 हजार छात्रो ने कनेक्शन विंडो का इस्तेमाल किया था। इस पर एनटीए ने कहा कि छात्र सिर्फ शहर बदल सकते है और कोई भी कैंडीडेट केंद्र नहीं चुन सकता । सेंटरनका चयन आलॉटमेंट सिस्टम द्वारा किया जाता है।सैंटर का अलॉक्शन परीक्षा से सिर्फ दो दिन पहले होता है।इसलिए किसी को नहीं पता कि कौन सा सैंटर मिलने वाला है। सीजेआई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सोमवार 22 जुलाई को सुबह 10:30 बजे नीट यूजी याचिकाकर्ताओ पर सुनवाई फिर से शुरू करेगी।इस बीच सीबीआई ने जांच का दायरा बढाते हुए पटना एम्स के 4 डाक्टरों को हिरासत में लिया है। सूत्रो के मुताबिक कुछ और डॉक्टरो तक दायरा बढ सकता है।

केजरीवाल सरकार 900 करोड़ रूपए के बजट से इस साल दिल्ली के गांवों में विकास कार्य करा रही है : गोपाल राय

सुषमा रानी

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार शहरों की तरह गांवों में भी हर मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात गुरुवार को दिल्ली के पर्यावरण एवं विकास मंत्री गोपाल राय ने गांवों के विकास कार्यो को गति देने के लिए मॉडल टाउन विधान सभा में आयोजित 'विकास सभा' में कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली के गांवों के विकास से संबंधित कार्यो के लिए सरकार ने 900 करोड़ रूपए का बजट रखा है। गोपाल राय ने बताया कि 10 करोड़ रूपए की लागत से मॉडल टाउन विधान सभा के गांवों में विकास कार्य किया किया जा रहा है। इस अवसर पर मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार गांवों में सड़कों, पार्कों, नालियों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग,

एमसीडी सहित अन्य सरकारी विभागों के माध्यम से किया जा रहा है।

विकास एवं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के सभी गाँवों में विकास कार्य कराने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया था। जिसके तहत दिल्ली के सभी गाँवों में विकास का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत सामुदायिक केंद्र, सड़कों, नालियों, जल निकाय, पार्क, श्मशान, खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली के गाँवो के विकास के लिए इस साल सरकार ने 900 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उन्होंने आगे बताया कि 10 करोड़ रूपए की लागत से मॉडल टाउन विधान सभा के गांवों में विकास कार्य किया जा रहा है। गोपाल राय ने कहा कि मॉडल टाउन विधान सभा के गांवों में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड द्वारा काफी काम करवा दिया गया है। उन्होंने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की अधिकारी को बचे हुए काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

गोपाल राय ने कहा कि विकास कार्यों में जनता की सहभागिता को लेकर यह विकास सभा का आयोजन किया गया है। जिसके माध्यम से गाँवों के लोगों को विकास कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि विकास प्रक्रिया में जनसहभागिता जरूरी है। इससे विकास कार्यों को गति मिलती है। उन्होंने कहा कि गाँवों के विकास कार्यो को गति देने के लिए यह विकास सभा का आयोजन किया गया है।

दिल्ली के मीलार्ड को भी साइबर ठगों ने लगाया चूना

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहने वाले रिटायर्ड एडीशनल सेशन जज जितेंद्र सिंह को भी साइबर ठगों ने नहीं बख्शा और लगा दिया लाखों का चूना। उत्तर पश्चिम जिला रोहिणी का साइबर पुलिस थाना, जज से ठगी मामले की जांच में जुट गया है। साइबर पुलिस टीम ने पता लगाया है कि वट्सऐप एकाउंट आखिर बार सिवान,बिहार में एक्टिव हुआ है ।फोन कॉल करने वाले की लोकेशन जमशेद पुर झारखंड मालूम चली है। दरअसल साइबर ठगो ने वट्सऐप कॉल को डायवर्ट कर ठगी को अंजाम दिया। पुलिस के आलाधिकारी के मुताबिक जगमीत सिंह सेखो नाम का शख्स उनके छोटे भाई चांद कुमार धाम का पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ में क्लासिकल था ।इनका छोटा भाई न्यूयार्क चला गया,जबकि सिंह सीखो की आईडी से इन्हें पता चला कि उनका जन्मदिन 10 जून को है। उन्होने उन्हें बर्थ डे विश का मैसेज भेजा। 12 जून को कनाडा से जगमीत सिंह सेखो का मैसेज आया कि वह इंडिया आ रहा है ।साथ ही लिखा कि वह 12.50 लाख रूपये भेज रहा है। इसके लिए जगमीत सिंह ने ब्लैंक चेक की फोटो कॉपी भेज दी। उसके बाद फिर कनाडा के कथित जगमीत सिंह सेखो का एक वट्सऐप मैसेज मिला। जिसमें उसने रॉयल बैंक की एक स्लिप भेजी ।जिसमें साढे 12 लाख रूपये लिखे

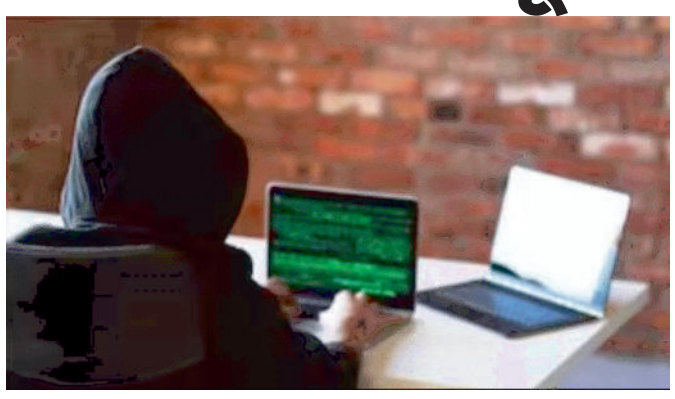

थे। इसके बाद कनाडा से जगमीत सिंह ने मेसेज भेज दिया कि उसको भारत में अपने ट्रैवल एजेंट कुंदन कुमार का फोन आया ।उसने अपनी बैंक डिटेल भेजी, जो पंजाब नेशनल बैंक मोतिहारी की थी। भरोसा होने के बाद कुंदन कुमार को 3.50 लाख रूपये भेज दिए, लेकिन उनको रॉयल बैंक से वो 12.50 लाख रूपये नहीं मिले ।बाद में पता चला कि जो बैंक एडवाइस भेजी गई थी, वो जाली थी। इसी बीच कनाडा से और ट्रैवल एजेंट की कई बार कॉल आए। साथ ही और रकम भेजने को कहा ।रकम नहीं भेजने पर ट्रैवल एजेंट ने पीडित को एक बार वॉयस मैसेज भी भेजा। जिसमें वह अधिक पैसे की डिमांड कर रहे थे ।ऐसा न करने पर वे धमकी देने लगे ।पीडित को शक हुआ। उन्होने कोई रकम नहीं.भेजी। फिलहाल नॉर्थ-वेस्ट जिले की रोहिणी साइबर सेल थाने की पुलिस ने संबंधित धाराओ में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जज ने वट्सऐप और टेलिकॉम सर्विस की भूमिका को भी जांच के दायरे में रखने को कहा है। टेलिकॉम सर्विस से भी पूछताछ की जाए कि माइक्रो सैकेंड में इनकी कॉल को किसी अज्ञात नंबर पर कैसे फारवर्ड कर दिया। वहीं जज जितेंद्र सिंह ने साइबर सेल टीम के प्रयास से अपने वट्सऐप का एक्सपस भी हांसिल कर लिया है। दरअसल मामला जज से जुडा होने के कारण साइबर पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया ।लेकिन इस बीच ठगो ने जज के दो दोस्त शोभना गुप्ता से 60 हजार, और नीलेश सिंहा से 35 हजार रूपये का भुगतान कर लिया था। इसी के बाद जज जितेंद्र सिंह ने डिवाइस से हजार स्पोर्ट सर्विस पर शिकायत दर्ज की।

अब कानूनी मदद के लिए नहीं भटकेंगे जरूरतमंद, सहायता करने पहुंचेंगे कानून के छात्र; जानिए क्या है पूरा प्लान

अभी आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े क्षेत्रों से जुड़े लोगों को किसी भी तरह की कानूनी मदद के लिए वकीलों के चैंबर के चक्कर काटने होते हैं लेकिन अब कानूनी मदद देने वाले खुद उनके पास चलकर पहुंचेंगे। इससे न सिर्फ कानून से अनभिज्ञ जरूरतमंद लोगों की मदद होगी बल्कि छात्रों को भी पढ़ाई के दौरान सीखने और समझने का मौका भी मिलेगा। जानिए क्या है पूरा प्लान...

नई दिल्ली। कानून की पढ़ाई कराने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों ने यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की सिफारिश को अपनाया तो आने वाले दिनों में आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े क्षेत्रों से जुड़े लोगों को किसी भी तरह की कानूनी मदद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कानूनी मदद देने वाले उनके पास खुद चलकर पहुंचेंगे। इससे न सिर्फ कानून से अनभिज्ञ कमजोर और पिछड़े लोगों की मदद होगी, बल्कि छात्रों को भी पढ़ाई के दौरान सीखने और समझने का मौका भी मिलेगा।

सिविल लाइन में डीडीए ने अक्रामक तरीके से गरीबों के घर तोड़े हैं

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दुर्गेश पाठक ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले 10 दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। ये तोड़फोड़ दिल्ली के भाजपा के सांसदों के तहत आने वाले विभागों द्वारा की जा रही है। कुछ दिनों पहले डीडीए ने सिविल लाइन इलाके में आक्रामक तरीके से हजारों लोगों के घर तोड़े और डीडीए के अधिकारी अभी भी उस इलाके में जाकर लोगों को धमकी दे रहे हैं कि अभी और घर तोड़े जाएंगे। वहीं, केंद्र सरकार के रेलवे विभाग ने बरार स्क्वायर में रेलवे ट्रैक के पास लोहा मंडी, बुद्ध नगर, इंदरपुरी की हजारों झुग्गियों को 22 जुलाई से पहले तोड़ने का नोटिस लगा दिया है। रेलवे विभाग भी भाजपा के सांसदों के अंतर्गत आता है।

उन्होंने कहा कि बुधवार को जब प्रेस वार्ता करके हमने इन कार्रवाइयों पर सवाल उठाए तो भाजपा के सांसद सीधा जवाब देने के बजाय फिर वही उल-जुलूल बाते दोहरा रहे हैं। बांसूरी स्वराज नई दिल्ली से भाजपा की सांसद है, बरार स्कावयर में रेलवे द्वारा लोटिस लगाए 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन वह एक बार भी वहां जाकर लोगों से नहीं मिलीं, न ही उन्हें ये आश्वासन दिया किया कि वह रेलवे विभाग से बात करेंगी और किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। लोगों से मिलना तो दूर, वो लोगों का फोन तक नहीं उठा रही हैं। उनके पीए भी फोन नहीं उठा रहे हैं, लोग किसी भी तरह से उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अगर लोगों को घर तोड़े जाते हैं तो इसकी जिम्मेदार बांसूरी स्वराज होंगी, क्योंकि उनके तहत आने वाला रेवले विभाग ही लोगों के घर तोड़ने का नोटिस दे रहा है। इसी तरह चांदनी चौक से भाजपा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल से भी किसी तरह का कोई

संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई सांसद इन कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है।

उन्होंने कहा कि 11 साल से दिल्ली में भाजपा के सांसद राज कर रहे हैं। इन्होंने इतने साल में कोई काम नहीं किया और अब दिल्ली को पूरी तरह से उजाड़ने में लगे हुए हैं। नई दिल्ली की सांसद बांसूरी स्वराज गायब हैं। हजारों लोगों के घर टूट जाएं, उजड़ जाएं लेकिन इन्हें अपनी राजनीति से फुरसत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवा भी गायब हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं है। चांदनी चौक में लोगों के घर टूटे हुए पांच दिन हो गए लेकिन वो किसी से मिलने तक नहीं गए।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मानती है कि ये तोड़फोड़ पूरी तरह से अवैध है। सिविल लाइंस में रह रहे ये लोग आजादी के समय से यहां रह रहे हैं। पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार के लोग वहां रह रहे हैं। ये लोग 70-80 सालों से वहां रह रहे हैं और आज उनके घर तोड़ दिए गए। किसके निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है? क्या ये एलजी साहब के निर्देश पर हुआ है, भाजपा के सांसदों के कहने पर हुआ है या केंद्र सरकार के मंत्री ने इसके निर्देश दिए थे? रेलवे किसके निर्देश पर उन घरों को तोड़ने के नोटिस लगा रहा है? इसके पीछे कौन है? क्या ये बांसूरी स्वराज के निर्देश पर हो रहा है या अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इन्हें सांसद बने करीब 50 दिन हो गए हैं, लेकिन ये लोग कोई काम नहीं करते हैं, केवल माला पहनकर फोटो खिचवाने जाते हैं। दिल्ली की जनता भाजपा से इस कार्रवाई का बदला लेगी। ये पूरी तरह से गलत है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इन दोनों मामलों के पीछे जो भी है उसकी जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों ने भाजपा के सांसदों को जिताकर भेजा है, इसलिए इन कार्रवाइयों को रोकना उनकी जिम्मेदारी है। हम ये मामला कोर्ट में लेकर गए हैं, हमें उम्मीद है वहां से भी न्याय मिलेगा, लेकिन भाजपा की ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है और ये दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश है। इसमें शामिल अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब साफ होगा कि भाजपा के सांसद भी मिले हुए हैं।

यीडा 205 लाख की लागत से बनाएगा भूमिगत जलाशय, सुंदरीकरण के कार्य पर भी होगा करोड़ों खर्च

नोएडा के सेक्टर 33 में यमुना प्राधिकरण भूमिगत जलाशय बनाने वाला है। इसके हो जाने से औद्योगिक सेक्टर में पानी की मांग पूरा हो सकेगा। सेक्टर में सड़क सीवर बिजली आदि के कार्य पहले ही हो चुके हैं। सुंदरीकरण के कार्य पर भी प्राधिकरण 354 .76 करोड़ रुपये खर्च करने वाला है। इसके लिए एजेंसी की तलाश की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण सेक्टर 33 में भूमिगत जलाशय (यूजीआर) बनाएगा। इसके जरिये औद्योगिक सेक्टर की पानी की मांग को पूरा किया जाएगा। प्राधिकरण ने जलाशय निर्माण के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक सेक्टरों में औद्योगिक इकाईयों के निर्माण के साथ ही ढांचागत सुविधाओं को पूरी तरह से विकसित करने में जुट गया है। सेक्टर में सड़क, सीवर, बिजली आदि के कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं।

निर्माण पर प्राधिकरण 205.57 लाख रुपये करेगा खर्च

सेक्टर 33 में भूमिगत जलाशय के निर्माण का काम भी शुरू होने जा रहा है। इस जलाशय की क्षमता बीस हजार किलोलीटर होगी। इसके निर्माण पर प्राधिकरण 205.57 लाख रुपये खर्च करेगा। इससे औद्योगिक इकाईयों की पानी की मांग को पूरा किया जाएगा।

सुंदरीकरण के कार्य पर प्राधिकरण 354.76 करोड़ रुपये करेगा खर्च

सेक्टर 33 में प्राधिकरण ने टाय पार्क के अलावा एमएसएमई उद्योग के लिए भूखंड आवंटित किए हैं। टॉय पार्क में आवंटियों ने इकाईयों का निर्माण शुरू हो चुका है। वहीं कायाकल्प योजना के तहत जूनियर हाई स्कूल आदि के सुंदरीकरण के कार्य पर भी प्राधिकरण 354.76 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

इसके लिए भी एजेंसी का चयन किया जा रहा है। प्राधिकरण सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि औद्योगिक सेक्टर में इसी साल करीब सौ औद्योगिक इकाईयां क्रियाशील हो जाएंगी।

कांवड़ियों की टी-शर्ट पर महादेव के साथ मोदी-योगी और बुलडोजर की छाप, दोगुनी कीमत पर हो रही बिक्री

परिवहन विशेष न्यूज

कांवड़ यात्रा 2024 को लेकर बाजार में चारों तरफ भगवा रंग की टी-शर्ट और गमछा छाए हुए हैं। टी-शर्ट पर महादेव की फोटो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपी है। सामान्य टी-शर्ट से कीमत दोगुनी होने के बावजूद इसकी बिक्री सबसे ज्यादा हो रही है। इन टी-शर्ट का स्टाक नहीं होने पर लोग इसके लिए एडवांस बुकिंग करा रहे हैं।

साहिबाबाद। भगवान शिव की पूजा-अर्चना का पावन माह सावन 22 जुलाई से पहले सोमवार के साथ शुरू हो जाएगा। शिव भक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए ट्रांस हिंडन के बाजार सज गए हैं। इस बार कांवड़ियों की टी-शर्ट पर मोदी-योगी व बुलडोजर की छाप दिखेगी।

बाजार में इन टी-शर्ट की धूम है। ट्रांस हिंडन में काला पत्थर रोड इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशांबी, राजेंद्रनगर, लाजपत नगर समेत ज्यादातर बाजार भगवा टी-शर्ट, गमछे से कांवड़ियों की वेशभूषा वाली सामग्री से सजे हुए हैं।

टी-शर्ट पर जय योगी बाबा की और जय महादेव लिखा है। विक्रेता हरेंद्र कुमार ने बताया कि इन टी-शर्ट की सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। जबकि इनकी कीमत सामान्य टी-शर्ट से लगभग दोगुनी है। जहां सामान्य टी-शर्ट 150 रुपये तक मिल रही है। वहीं योगी-मोदी की तस्वीर छपी टी-शर्ट की कीमत 400 रुपये तक है। इसके बाद भी इन टी-शर्ट की खूब डिमांड है।

टी-शर्ट खत्म होने पर करा रहे बुकिंग

काला पत्थर रोड पर स्टाल लगाकर कांवड़ से जुड़ी सामग्री विक्रेता अनुज ने बताया कि मोदी की तस्वीर छपी टी-शर्ट खत्म हो गई हैं। इसके लिए 50 से अधिक लोगों ने एडवांस बुकिंग करा ली है। इसके लिए लोगों ने पैसे भी पहले से जमा कर दिए हैं।

माल लेने के लिए जल्द ही दिल्ली जाएंगे। सावन शुरू होने से पहले उन्हें टी-शर्ट उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा कांवड़ियों से संबंधित टोपी, लोअर, बनियान, अंडरवियर, बैग सहित होजरी का अनेक सामान की एडवांस बुकिंग हो रही है।

150 से 400 रुपये तक है एक टी-शर्ट की कीमत

दुकानदारों ने बताया कि सावन शुरू होने से पहले ही कांवड़ियों की वेशभूषा से संबंधित कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। एक टी-शर्ट की कीमत 150 से 400 रुपये तक है। इसी तरह लोअर की कीमत 200 से 400 रुपये तक है। इसके अलावा टोपी, बनियान, बैग व चश्मों की कीमत भी गुणवत्ता के हिसाब से निर्धारित है।

नगर निगम ने शुरू की सफाई

नगर निगम ने कांवड़ मार्ग के आसपास साफ सफाई शुरू कर दी है। बुधवार को वैशाली सेक्टर छह व पांच की पुलिया के पास हिंडन नहर रोड की सफाई की। कांवड़ मार्ग के किनारे डाले जा रहे कूड़े को उठाया गया। निगम के अधिकारियों का कहना है कि अन्य इलाकों में भी साफ-सफाई की जाती है।

कांवड यात्रा के लिए कौन सा सामान कितने का मिल रहा

टी-शर्ट 150 से 400 रुपये
लोअर 200 से 400 रुपये
गमछा 50 से 200 रुपये
टोपी 50 से 150 रुपये
बैग 100 से 250 रुपये

पीएम किसान सम्मान निधि में अब नहीं कर पाएंगे धांधली, सरकार ने कर ली तैयारी; किसानों के लिए बनेगा अब ये नया कार्ड

प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले काफी संख्या में ऐसे लोगों का नाम सामने आया है। जो इस योजना में शामिल ही नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने योजना का लाभ लिया। सम्मान निधि से करोड़पति भूमिहीन सेंध नहीं लगा पाएंगे। अब सही किसानों का पता लगाने के लिए बिना किसान कार्ड बनाया जाएगा।

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले काफी संख्या में ऐसे लोग चिह्नित हुए हैं, जो अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ उठा रहे थे। मामला पकड़ में आने के बाद शासन ने ऐसे किसानों से वसूली के आदेश दिए।

जांच में सामने आया कि ऐसे किसानों ने भी योजना का लाभ उठाया, जो भूमिहीन थे। यह हाल केवल सम्मान निधि योजना का नहीं बल्कि कृषि संबंधी अन्य योजनाओं का भी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अपात्रों पर नकेल कसने के लिए किसान कार्ड बनेगा। जिसके पास कार्ड होगा, वही किसान योजना की पात्रता में शामिल होगा।

कार्ड नहीं तो पात्र नहीं

गांवों में शिविर लगाकर कृषि विभाग दस्तावेजों की जांच कर कार्ड बनाने के लिए किसानों का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज करेगा। पोर्टल पर किसान का आधार कार्ड, खेत का रकबा, खसरा नंबर, मोबाइल नंबर, ईकेवाइसी बुआई की जाने वाली कम से कम दो फसल आदि का पूरा ब्योरा दर्ज होगा।

इसके बाद एक किसान को यूनीक नंबर जारी होगा। नंबर के जरिये किसान का पूरा विवरण आन लाइन उपलब्ध होगा। किसान को कार्ड के जरिये ही दिसंबर से पीएम सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

करोड़पति भूमिहीनों ने लगा दी थी सम्मान निधि में सेंध

वित्तीय वर्ष 2022 में सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले ऐसे किसान भी पकड़ में आए जिनकी जमीन ग्रेटर नोएडा, नोएडा व यमुना प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण कर चुका है। उसके बावजूद किसान योजना का लाभ उठा रहे थे। पिछले साल अपात्रों की छटनी में 1719 ऐसे लाभार्थी भी सामने आए जो आयकर दाता भी थे।

आधार की तर्ज पर किसान कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए गांवों में शिविर लगाकर कार्ड बनाने के लिए मोबाइल ऐप पर पंजीकरण किया जाएगा। बिना किसान कार्ड के विभागीय योजना में आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

यह होगा फायदा

अपात्र योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

किसान का पूरा विवरण ऐप पर होगा।

कृषि ऋण लेने के लिए बार-बार रिकार्ड नहीं देना पड़ेगा।

लाभार्थियों का सत्यापन, कृषि उत्पाद का विवरण आदि मामलों में सहूलियत होगी।

फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड आसानी से बन सकेगा।

आपदा के दौरान किसान की क्षतिपूर्ति का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

फसल बीमा कराना आसान होगा।

जिले में पंजीकृत किसानों की संख्या- 57 हजार 77

सम्मान निधि के तहत 2022 में मिले अपात्र - 1719

पिछले वित्तीय वर्ष में मिले अपात्र - 817

जिले में किसानों की संख्या

दनकौर -17958

जेवर - 16881

बिसरख- 6212

दादरी -12431

17 साल की नाबालिग से शादी कर रहा था 35 साल का शख्स, फेरों से एक घंटे पहले लड़की को...

शैक्षिक अभिलेख और आधार कार्ड में नाबालिग की उम्र 18 से कम है। शादी के कार्यक्रम के बारे में किसी को जानकारी नहीं हो इस कारण लड़की के स्वजन ने पूरे कार्यक्रम का आयोजन घर से कुछ ही दूरी पर एक बड़े घर में किया था। सिर्फ 15 लोगों को शादी का निमंत्रण दिया गया था। शादी का खर्च वर पक्ष ही उठा रहा था।

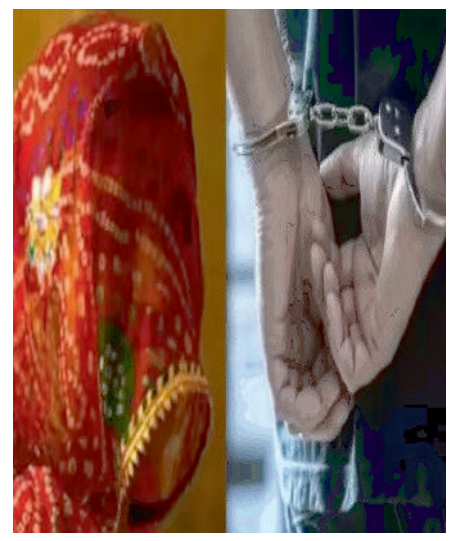

नोएडा। चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 पर मिली शिकायत के बाद चाइल्ड लाइन ने एक नाबालिग को वधू बनने से रोका है। चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक अदनान उस्मानी ने बताया कि एक व्यक्ति से सेक्टर-45 सदरपुर गांव में बुधवार को नाबालिग की शादी कराए जाने की सूचना मिली थी।

जिला प्रोबेशन अधिकारी आशीष कुमार ने चाइल्ड लाइन को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। प्रकरण में न्याय पीठ को पत्र के माध्यम से बाल विवाह रुकवाने का अनुरोध किया गया। बुधवार शाम चार बजे नाबालिग की शादी होनी थी, लेकिन शादी से करीब एक घंटे पहले टीम ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाकर स्वजन के सुपुर्द किया।

मां-पिता के दबाव में शादी के लिए तैयार हो गई नाबालिग

सदरपुर की किशोरी के पिता सेक्टर-44 में ही परचून की दुकान हैं। वह साप्ताहिक बाजार में भी दुकान लगाते हैं। उनकी दो बेटियां और एक बेटा हैं। जिस नाबालिग की शादी हो रही थी। वह सबसे बड़ी बेटी है। आर्थिक तंगी की वजह से स्वजन 17 साल की बेटी की शादी 35 साल के व्यक्ति से कराने को तैयार हो गए। लड़के पक्ष वालों को नहीं पता था कि लड़की नाबालिग है।

युवक के नाम चार मकान है, जिसका किराया आता है। स्वजन को लगा कि अगर अच्छे परिवार में बेटी की शादी हो जाएगी तो उसे आर्थिक तंगी से नहीं जूझना पड़ेगा। स्वजन ने बहला फुसलाकर नाबालिग को शादी के लिए राजी कर लिया। मां-पिता के दबाव में नाबालिग शादी के लिए तैयार हो गई। नाबालिग ने आठवीं तक की पढ़ाई की है।

इस वित्तीय वर्ष में तीन को बालिका वधू बनने से रोका

चाइल्ड लाइन की ओर से इस वित्तीय वर्ष में तीन नाबालिग को बालिका वधू बनने सो रोका गया है। बीते माह सेक्टर-123 में शादी से एन वक्त पहले एक युवती के फरार हो जाने के बाद घरवाले स्वजन बेइज्जती से बचने के लिए 13 साल की नाबालिग को फेरो के मंडप में बैठाना चाहते थे।

जानकारी होने पर चाइल्ड लाइन ने बाल विवाह रुकवाया था। इसी तरह दनकौर गांव में एक किशोरी की उम्र शादी के दौरान दो माह कम होने पर विवाह को रोका गया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत किसी भी बालिका की आयु 18 वर्ष एवं बालक की आयु 21 वर्ष पूरा होने से पहले करना कानून अपराध है।

फिर आतंकी हमलें, सैनिकों का बलिदान व्यर्थ न जाये

ललित गर्ग

ज्यादा चिन्ताजनक यह है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी न केवल घुसपैठ कर रहे हैं, बल्कि अपनी गतिविधियों को अंजाम देने और इस क्रम में सेना को निशाना बनाने में भी सफल हो रहे हैं। सरकार को उन खूनी हाथों को खोजना होगा अन्यथा खूनी हाथों में फिर खुजली आने लगेगी।

लगातार जम्मू-कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाएं चिन्ता का कारण बन रही है। डोडा जिले में एक आतंकी हमले में कैप्टन समेत सेना के चार जवानों और जम्मू कश्मीर के एक पुलिसकर्मी का बलिदान अब यही दर्शा रहा है कि शांति एवं अमन की ओर लौटा जम्मू-कश्मीर एक बार फिर आतंकवादी आघातकारी घटनाओं की भेंट चढ़ रहा है, इन घटनाओं का माकुल जबाव नहीं दिया गया तो यह घाटी एक बार फिर खूनी घाटी बन जायेगी। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कठुआ में एक सैन्य अफसर सहित पांच जवान आतंकियों का निशाना बन गए थे। इसके पहले भी जम्मू संभाग में ही सेना के कई जवान आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। ये बहुत चिंतित करने वाले त्रासद एवं घिनौने घटनाक्रम हैं कि पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी के साथ-साथ जम्मू संभाग में भी आतंकियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हाल की कुछ घटनाओं से तो यह भी लगता है कि आतंकियों ने जम्मू संभाग को अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना लिया है। एक ऐसे समय जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी हो रही है, तब आतंकियों का सक्रिय होना और सफलतापूर्वक अपने मनसूबों को कामयाब करना गंभीर चिंता का विषय है।

ज्यादा चिन्ताजनक यह है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी न केवल घुसपैठ कर रहे हैं, बल्कि अपनी गतिविधियों को अंजाम देने और इस क्रम में सेना को निशाना बनाने में भी सफल हो रहे हैं। सरकार को उन खूनी हाथों को खोजना होगा अन्यथा खूनी हाथों में फिर खुजली आने लगेगी। हमें इस काम में पूरी शक्ति और कौशल लगाना होगा। आदमखोरों की मांद तक जाना होगा। अन्यथा हमारी खोजी एजेंसियों एवं सेना की काबिलीयत पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा कि कोई दो-चार व्यक्ति कभी भी पूरे प्रांत की शांति और जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर सकते हैं, हमारी संवेदनाओं को झकझोर सकते हैं। संवेदनाओं एवं भावनाओं को झकझोर भी रहे हैं, जब आतंकवादी हमलों में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे घर की ड्योढ़ी पर आते हैं तब कारुणिक माहौल को देखकर दिल दहल उठता है क्योंकि देश के लिए अपना सर्वोच्च लुटा देने वाला जवान किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का पिता होता है। हर आंख में आंसू होते हैं। किसी की गोद, किसी की मांग सूनी हो जाती है। देशवासी सोचने को विवश हैं कि वे शोक संत्पत परिवार के साथ करुणा और पीड़ा को कैसे बांटें।

डोडा वारदात की जिम्मेदारी लेने वाले 'कश्मीर टाइगर्स' जैसे आतंकी संगठनों की ताजा बौखलाहट की एक बड़ी वजह जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली को लेकर बढ़ी सरगर्मी है। राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए अगले चंद महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में, आतंकियों की बेचैनी समझी जा सकती है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में घाटी में लोग मतदान केंद्रों पर उमड़ पड़े और दशकों पुराना रिकॉर्ड टूटा, अगर विधानसभा चुनाव में लोगों का उत्साह और बढ़ा, तो जिन 'स्लीपर सेल्स' की बदौलत वे दहशत का अपना पूरा कारोबार चलाते हैं, वे भी मुख्यधारा के प्रति आकर्षित होकर, उनके खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने घाटी के बजाय जम्मू संभाग में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया जा सके और सीमा पार के आकाओं से मदद हासिल करने का सिलसिला जारी रहे।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान से पाकिस्तान बौखलाया है। इसी का परिणाम है लगातार हो रहे आतंकी हमलें। इन हमलों ने आंतरिक सुरक्षा के लिये नये सिरे से चुनौती पैदा की है। जम्मू में रियासी, कठुआ और डोडा के आतंकी हमले चिन्ता का बड़ा कारण बने है। जम्मू-कश्मीर का माहौल सुधरने के बाद वहां के बाजार, पर्यटक स्थल गुलजार हुए हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। इसलिए देशद्रोही नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति आए और वहां पर निर्वाचित सरकार काम करे। केन्द्र में गठबंधन वाली मोदी सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती है। क्या इन आतंकी घटनाओं को केन्द्र सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है? जो सरकार पाकिस्तान में घूस कर बदला ले सकती है, वह सरकार अब तक शांत क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। आतंकी जिस तरह अपनी रणनीति बदलकर सुरक्षा बलों को कहीं अधिक क्षति पहुंचाने में समर्थ दिखने लगे हैं, वह किसी बड़ी साजिश का संकेत है। एक ओर सीमा पार से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण करना होगा, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को नए सिरे से सबक भी सिखाना होगा। यह इसलिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में आतंकी हमलों में बलिदान होने वाले सैनिकों की संख्या कहीं अधिक बढ़ी है।

पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठानों की मदद से यह आतंक का खेल फिर शुरू कर रहा है। कहीं न कहीं दिल्ली में बनी गठबंधन सरकार को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पाक पोषित आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में शांति एवं अमन को कायम नहीं रहने देंगे। एक आंकड़े के अनुसार पिछले तीन वर्ष में करीब 50 जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा है। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। आतंक को करारा जवाब केवल तभी नहीं दिया जाना चाहिए, जब एक साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को बलिदान देना पड़े। वास्तव में हमारे एक भी सैनिक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। डोडा की घटना के बाद यह जो कहा जा रहा है कि सैनिकों के बलिदान का बदला लिया जाएगा, उसे न केवल पूरा करके दिखाया जाना चाहिए, बल्कि आतंकियों, उनके आकाओं और उन्हें सहयोग-समर्थन देने वालों पर ऐसा करारा प्रहार किया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी हरकतों से हमेशा के लिए बाज आएं। पाकिस्तान भले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा हो, लेकिन वह जम्मू कश्मीर में पहले की तरह ही आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। उसकी घरेलू व विदेश नीति 'कश्मीर' पर ही आधारित है। चूंकि इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन उसे उकसाने में लगा हुआ होगा, इसलिए भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा।

केन्द्र सरकार ने कश्मीर में विकास कार्यों को तीव्रता से साकार किया है, न केवल विकास की बहुआयामी योजनाएं वहां चल रही है, बल्कि पिछले 10 सालों में कश्मीर में आतंकमुक्त करने में भी बड़ी सफलता मिली है। बीते साढ़े तीन दशक के दौरान कश्मीर का लोकतंत्र कुछ तथाकथित नेताओं का बंधुआ बनकर गया था, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये जो कश्मीर देश के माथे का ऐसा मुकुट था, जिसे सभी प्यार करते थे, उसे डर, हिंसा, आतंक एवं दहशत का मैदान बना दिया। लेकिन वहां विकास एवं शांति स्थापना का ही परिणाम रहा कि चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेकर लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया। बढ़ती आतंकी घटनाओं पर गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर बनाए हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुरक्षा बल आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देगा लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा बलों को आतंकियों के प्रति अपनी रणनीति बदलनी होगी और आतंकी जिन बिलों में छिपे होंगे उन्हें वहां से निकालकर ढेर करना होगा। आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी करनी होगी और साथ ही आतंकियों के मददगारों की भी पहचान करनी होगी, तभी आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया जा सकता है।

पुलिस के आला अधिकारी यदि यह कह रहे हैं कि घाटी के नागरिक समाज में पाकिस्तानी 'घुसपैठ' को बढ़ावा देने में कतिपय राजनीतिक दलों का रुख भी जिम्मेदार रहा है, तो क्या यह आधारहीन है? इसका मुकाबला हर स्तर पर हम एक होकर और सजग रहकर ही कर सकते हैं। यह भी तय है कि बिना किसी की गद्दारी के ऐसा संभव नहीं होता है। ताजा आतंकी हमलों के विकराल रूप कई संकेत दे रहे हैं, उसको समझना है। कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसका उत्तर देना है। यह पाकिस्तान का बड़ा षड़यंत्र है इसलिए इसका फैलाव भी बड़ा हो सकता है। ये घटनाएं चिल्ला-चिल्ला कर कह रही हैं हमारी खोजी एजेन्सियों से, हमारी सुरक्षा व्यवस्था से कि वक्त आ गया है अब जिम्मेदारी से, सख्ती से और ईमानदारी से जम्मू-कश्मीर को संभालें।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर

सैमसंग ने टेस्ला वाहनों के लिए शुरू की ऊर्जा प्रबंधन सेवा

परिवहन विशेष न्यूज

सियोल: उद्योग सूत्रों ने बुधवार, 17 जुलाई को बताया कि सैमसंग ने घरेलू कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी रणनीतिक साझेदारी के तहत अमेरिका में टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऊर्जा प्रबंधन सेवा शुरू की है।

सूत्रों के अनुसार सैमसंग का 'स्मार्टथिंग्स एनर्जी' प्लेटफॉर्म अब अमेरिका में टेस्ला ड्राइवरों के लिए उपलब्ध है, जिससे वे अपनी ईवी बैटरी की चार्जिंग स्थिति और सौर पैनलों द्वारा उत्पन्न बिजली की निगरानी और नियंत्रण कर सकेंगे।

टेस्ला ऐप के पावरवॉल स्टॉर्म वॉचर फ़ंक्शन के साथ समन्वयित, एआई-संचालित स्मार्टथिंग्स कनेक्टिविटी प्लेटफ़ॉर्म, तूफान और भारी बर्फबारी जैसी चरम मौसम स्थितियों के मामले में उपयोगकर्ताओं को उनके कनेक्टेड सैमसंग टीवी और मोबाइल डिवाइस पर अलर्ट करता है।

नई सेवा दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गजों के बीच नए गठबंधन का हिस्सा है, जिसकी घोषणा इस वर्ष की शुरुआत में वैश्विक आईटी प्रदर्शनी सीईएस 2024 में की गई थी।

सैमसंग-टेस्ला सहयोग सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मार्टथिंग्स एनर्जी को टेस्ला की ऊर्जा उत्पाद श्रृंखला के साथ एकीकृत करने पर केंद्रित है, जिसमें पावरवॉल होम बैटरी, सोलर इन्वर्टर, वॉल कनेक्टर चार्जिंग समाधान और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि वह भविष्य में अमेरिका के बाहर भी इस सेवा का विस्तार करने की योजना बना रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्या चाहती है ऑटो इंडस्ट्री

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्रदर्शन साल दर साल बेहतर होता जा रहा है। राजीव बजाज जैसे कई दिग्गज लगातार ऑटो इंडस्ट्री पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ बोलते रहे हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से ऑटो इंडस्ट्री को भी कई उम्मीदें हैं।

ऑटोमोबाइल सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाएगी। इसके साथ ही फेम 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पॉलिसी के ऐलान की भी उम्मीद है। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम का मानना है कि वित्त मंत्री जीडीपी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बड़े ऐलान करेंगी। ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ अर्थव्यवस्था की ग्रोथ से जुड़ी हुई है। सरकार ईवी को बढ़ावा देने के साथ ही पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की नीति भी स्पष्ट करेगी। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए जाने की उम्मीद है।

ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का संगठन यानी एक्मा भी जीएसटी में छूट समेत मशीनरी पर सहायता बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। संगठन का मानना है कि इस बजट से ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम जैसे उपाय भविष्य में भी जारी रहेंगे। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में पीएलआई स्कीम की अहम भूमिका रही है। इसके साथ ही इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के अपने प्रयास जारी रखेगी।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा ने वित्त मंत्री से अपील की है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को वाहन खरीद पर छूट दी जाए। इससे न सिर्फ उद्योग को फायदा होगा बल्कि रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। फाडा ने कॉरपोरेट टैक्स में भी छूट की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में हाइब्रिड वाहनों पर छूट का ऐलान किया है। ऐसे में बजट में ईवी और हाइब्रिड वाहनों पर और छूट का ऐलान होने की उम्मीद है। इससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा।

19 जुलाई को होगा टाटा कर्व के ईवी वर्ज़न का आधिकारिक खुलासा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स 19 अगस्त को कर्व के ईवी वर्जन से आधिकारिक तौर पर पर्दा उठाएगी। जहां कंपनी टाटा कर्व के ईवी वर्जन के प्रोडक्शन-रेडी मॉडल को सार्वजनिक तौर पर पेश करेगी। टाटा इसे भारत में 7 अगस्त को लॉन्च करेगी। ऐसे में इसकी अनऑफिशियल बुकिंग भी शुरू हो गई है। इच्छुक खरीदार टाटा के किसी भी अधिकृत डीलर से संपर्क करके और 21,000 रुपये का टोकन देकर इस नई एसयूवी को बुक कर सकते हैं। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो टाटा कर्व ईवी में स्प्लिट हेडलैंप होंगे। इसकी ग्रिल काफी हद तक सफारी जैसी ही दिखती है। साथ ही इसमें स्लोपिंग रूफलाइन, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल, नए अलॉय व्हील, साइड में कर्व्ड टेललाइट्स होंगे। इसके अलावा टेलगेट पर कर्व ईवी की बैजिंग भी देखने को मिलेगी। फीचर्स की बात करें तो कर्व ईवी में कई आधुनिक फीचर्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी कंट्रोल के लिए टचस्क्रीन बटन, एडीएएस सूट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टाटा लोगो के साथ टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्व ईवी को 56kWh क्षमता के दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा। अनुमान है कि इसके बाद कर्व ईवी एक बार फुल चार्ज होने पर 550 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकेगी।

अपने खास अंदाज से करें काइनेटिक ज़िंग का अनुभव और लुत्फ उठायें पुरीसंस के शोरूम पर

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। काइनेटिक ग्रीन ज़िंग एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो अपनी तेज़ परफॉरमेंस और बेहतरीन फीचर्स से प्रभावित करता है। अपनी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ यह स्कूटर आपको एक आरामदायक सवारी देता है, जो शहर की सड़कों पर चलने के लिए एकदम सही है।

ज़िंग का कॉम्पैक्ट साइज़ इसे तंग जगहों पर चलाना और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पार्क करना आसान बनाता है। लंबे समय तक चलने वाली बैटरी अच्छी रेंज देती है, जिससे आप बिना किसी चिंता के अपना दैनिक आवागमन पूरा कर सकते हैं।

स्टाइलिश डिज़ाइन और आरामदायक सीटिंग इसके प्रदर्शन को और बेहतर बनाती है। काइनेटिक ग्रीन ज़िंग शहरी निवासियों के लिए एक विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है।

काइनेटिक ज़िंग का अनुभव करने के लिए, आप चंडीगढ़ में पुरीसंस के शोरूम पर जाकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में आई गिरावट! शहरी परिवहन के लिए कंपनी ने लिया बड़ा फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपने थ्री-व्हीलर सब्सिडियरी सेगमेंट के पॉपुलर प्रोडक्ट ग्रीव्स अल्ट्रा सिटी की कीमत में कटौती का ऐलान किया है। ग्राहकों की भारी मांग और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद अब कंपनी ने इस प्रोडक्ट की कीमत कम कर दी है। कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बेस्ट इन क्लास फीचर्स के साथ आता है। इसमें ग्राहक को कंफर्ट, एफिशिएंसी और इनोवेशन का कॉम्बिनेशन मिलता है। आपको बता दें कि कंपनी ने इस प्रोडक्ट को साल की शुरुआत में लॉन्च किया था और तब से इस प्रोडक्ट को ग्राहकों का खूब प्यार मिल रहा है।

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अल्ट्रा सिटी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा रेंज देने वाला उत्पाद है। यह वाहन एक बार चार्ज करने पर 160 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करता है। इसमें 10.8 kwh की लिथियम-आयन बैटरी और 9.6 kW की मोटर लगी है। यह मोटर 49 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क जनरेट करती है।

कंपनी ने इस प्रोडक्ट में हिल होल्ड असिस्ट समेत कई फीचर्स दिए हैं, ताकि ड्राइवर की राइड आरामदायक हो और शहरी और अर्ध-शहरी सड़कों पर कोई दिक्कत न आए। फीचर्स की बात करें तो इस थ्री-व्हीलर में 6.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन और नेविगेशन में मदद करता है। कंपनी ने बैटरी पर 3 साल की वारंटी दी है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के निदेशक विजय कुमार ने कहा कि कंपनी शहरी परिवहन में क्रांति लाने के लिए तैयार है। हमारा ध्यान टिकाऊ और कुशल गतिशीलता समाधान प्रदान करना है।

प्लग एन राइड मोटर्स ने ईएलएस इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। प्लग एन राइड मोटर्स के संस्थापक व सीईओ ज़फर इक़बाल ने ईएलएस इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स के संस्थापक मुकेश गोयल के साथ वाहन की चोरी से सुरक्षा और पहचान के लिए एक सहयोगी ढांचा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

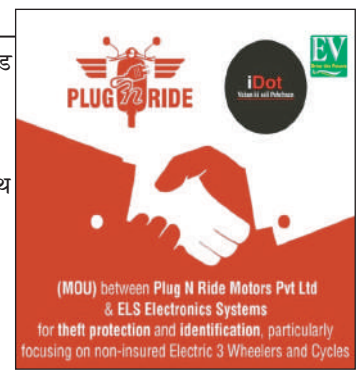

एमओयू का उद्देश्य चोरी-रोधी सुरक्षा और पहचान के लिए एक सहयोगी ढांचा स्थापित करना है, विशेष रूप से बिना बीमा वाले इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों और साइकिलों पर ध्यान केंद्रित करना हैं। सर्वेक्षण लागत को कम करने और ईवी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के मिशन के साथ, उत्पाद पहले से ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 935 (ई) के माध्यम से विस्तृत है और एआरएआई द्वारा एआईएस 155 के रूप में जारी अधिसूचना द्वारा सूचित किया गया है।

जफर इकबाल ने कहा कि प्लग एन राइड मोटर्स "आईडीओटी" एसेट आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से उद्योग के भीतर इस तकनीक को लागू करने में अग्रणी होगी। यह अभूतपूर्व पहल बड़े पैमाने पर चोरी के दावों को काफी हद तक कम करने के लिए तैयार है।

मुकेश गोयल ने इस तकनीक को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला और साथ ही कहा कि यह तकनीक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में इसका सफल कार्यान्वयन हो रहा है। गोयल ने इस तकनीक को "मेक इन इंडिया" पहल में इसे शामिल करने के महत्व पर जोर दिया।

सुजुकी का फोकस इलेक्ट्रिक वाहन के साथ हाइब्रिड पर

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सुजूकी मोटर कॉर्पोरेशन ने कहा कि ईंधन बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन 'आदर्श स्थिति' हो सकती है मगर जब तक गैर-जीवाश्म ईंधन देश भर में उपलब्ध नहीं होता है तब तक के लिए हाइब्रिड कारें 'सर्वश्रेष्ठ समाधान' हैं।

सुजुकी मोटर ने अपने प्रेजेंटेशन में अनुमान लगाया है कि भारतीय वाहन बाजार में ईवी, हाइब्रिड कार और पेट्रोल-डीजल कारों की हिस्सेदारी 2035 तक करीब 33-33 फीसदी होगी। भारत ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश बनने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़े कदम उठाए गए हैं।

जापानी ऑटो दिग्गज टोयोटा और मारुति सुजुकी हाइब्रिड कारों पर करों में कटौती की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि अकेले ईवी कार्बन उत्सर्जन को कम करने का बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी घरेलू कंपनियां इस तरह की कर कटौती का विरोध कर रही हैं।

उनका कहना है कि ईवी पर पूरी ताकत से जोर देकर ही भारत सही मायने में कार्बन उत्सर्जन घटा सकता है। वाहन उद्योग में यह मतभेद उत्तर प्रदेश सरकार के 5 जुलाई के एक फैसले से और उभरकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड वाहनों पर लगने वाले 8 से 10 फीसदी पंजीकरण शुल्क में छूट देने का निर्णय किया है।

सुजुकी मोटर ने कहा, 'गैर-जीवाश्म ईंधन के व्यापक उपयोग के साथ ऊर्जा बचत के मामले में ईवी आदर्श समाधान होगा। हम अगले साल से बाजार में ईवी पेश करेंगे और विद्युतीकरण में यथासंभव कम ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा देंगे। हमने बैटरी के उपयोग की आवश्यकता को कम करने के लिए लीन-बैटरी इलेक्ट्रिक तकनीक विकसित की है। जब तक गैर-जीवाश्म ईंधन पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक हाइब्रिड ईवी सबसे अच्छा समाधान है।'

कंपनी ने कहा, 'भारत में लगातार एथनॉल और कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) वाले वाहन पेश किए जा रहे हैं।' एसएमसी ने सुरक्षित ड्राइविंग की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हर देश की सड़क और ड्राइविंग स्थितियों के अनुरूप ड्राइवर सहायता प्रमाली (एडीएएस) तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है। इसने कहा, 'सुजूकी के प्रमुख बाजार भारत में यातायात की अनूठी स्थिति और भीड़भाड़ के कारण जापानी समाधानों को लागू करना मुश्किल हो जाता है।

भारत में सुजूकी के 40 वर्षों की उपस्थिति का लाभ लेते हुए हम एडीएएस विकसित करने और पेश करने की योजना बना रहे हैं, जो भीड़भाड़ वाली सड़कों पर भी अच्छा प्रदर्शन करे।' भारत में मारुति सुजूकी के वाहन का औसत वजन 933 किलोग्राम रहता है, जबकि अन्य भारतीय विनिर्माताओं के वाहन 1,333 किलोग्राम तक के होते हैं। कम वजन विनिर्माण और ड्राइविंग के दौरान कम ऊर्जा खपत की ओर इशारा करता है।

एसएमसी ने कहा कि उनकी कारों में सॉफ्टवेयर अपडेट वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीकों से हो सकेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वह उपयोगकर्ताओं के अनुकूल है। एसएमसी ने यह भी कहा है कि भारत में वह पुरानी कारों के लिए संग्रहण प्रणाली बनाने पर विचार कर रही है और उसने अपना कबाड़ कारोबार भी तैयार करना शुरू कर दिया है। फिलहाल भारत में करीब 21 फीसदी बिजली गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पैदा होती है।

पूजा का विधान

सिद्धगुरु प्रमोद जी

परमात्मा को पाने के कई मार्ग हैं, हजारों-हजार मार्ग हैं, और सब सही हैं। कोई मार्ग गलत नहीं है, कोई मार्ग किसी से कमतर नहीं है। दुनिया भर के हजारों धर्म अपने-अपने तरीके से परमात्मा को पाने का मार्ग बताते हैं। मैं किस परिवार में पैदा हुआ, वह परिवार किस देश के किस राज्य के किस शहर में रहता है, उस देश, उस राज्य और उस शहर की परंपराएं कैसी हैं, परिवार की संस्कृति क्या है, इन सबका असर मेरी सोच पर पड़ेगा।

जब हमने अनावश्यक संग्रह का लालच छोड़ दिया और हममें सेवा का भाव आ गया तो हम परमात्मा के नजदीक हो गए। जब हमने परमात्मा पर विश्वास करना आरंभ किया और अपने विश्वास का विश्वास किया, तो हम परमात्मा के नजदीक हो गए। 'सहज संन्यास मिशन' में हम यही सीखते हैं कि सहज जीवन जियें, परमात्मा से प्रेम करें, और इस ब्रह्मांड के हर जड़-चेतन वस्तु और प्राणी को परमात्मा का स्वरूप जानकर प्रेममय हो जाएं तो हम घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी संन्यासी ही हैं। निश्छल प्रेम, हर किसी से प्रेम, बिना कारण, बिना आशा के हर किसी से प्रेम'

परमात्मा को पाने के कई मार्ग हैं, हजारों-हजार मार्ग हैं, और सब सही हैं। कोई मार्ग गलत नहीं है, कोई मार्ग किसी से कमतर नहीं है। दुनिया भर के हजारों धर्म अपने-अपने तरीके से परमात्मा को पाने का मार्ग बताते हैं। मैं किस परिवार में पैदा हुआ, वह परिवार किस देश के किस राज्य के किस शहर में रहता है, उस देश, उस राज्य और उस शहर की परंपराएं कैसी हैं, परिवार की संस्कृति क्या है, इन सबका असर मेरी सोच पर पड़ेगा। मेरी शिक्षा-दीक्षा कहां हुई, मुझे कौनसे अध्यापक मिले, मेरी संगत कैसी थी, इन सबका भी असर मेरी सोच पर पड़ेगा और मैं वैसा ही विश्वास करने लगूंगा। उसी से यह तय होगा कि मैं परमात्मा में ही विश्वास करता हूं या नहीं करता, और यदि परमात्मा में विश्वास करता हूं तो परमात्मा को पाने के लिए कौनसा मार्ग चुनता हूं। यही कारण है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि परमात्मा एक है, पर परमात्मा को पाने के रास्ते हजारों हैं और सभी सही हैं। श्रीमद्भगवद् गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का जिक्र किया है। हम अपनी संस्कृति, अपनी आयु, अपने स्वास्थ्य, अपनी पसंद और अपनी सुविधा के मुताबिक कोई भी एक मार्ग चुन लें या सबके मिश्रण से परमात्मा को पाने की कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अन्य देशों के अन्य धर्मों के मानने वाले लोग अपनी पसंद और सुविधा के मुताबिक कोई अन्य मार्ग चुनें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता।

बहुत पहले मेरे पिता जी ने मुझे एक कथा सुनाई थी जिसमें जिक्र है कि इजरायल में जब यहूदियों पर अत्याचार बढ़ गए और उनका कत्लेआम होने लगा तो हसीदिक यहूदी धर्म के संस्थापक रहस्यवादी धर्मगुरू रब्बी इजरायल बेन एलिएजर जिन्हें बाल शेम तोव के नाम से भी जाना जाता है, ने जंगल में जाकर पवित्र अग्नि प्रज्वलित की और एक विशिष्ट प्रार्थना पढ़ी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर परमात्मा ने चमत्कार किया और यहूदियों का कत्लेआम रुका। बाद में उनके प्रधान शिष्य मेजेरिच के डोर बेर बेन अब्राहम, जिन्हें मेजेरिच के मैगिड के नाम से भी जाना जाता है, ने उसी जंगल के उसी खास स्थान पर जाकर प्रार्थना करते हुए परमात्मा से निवेदन किया कि मुझे नहीं पता कि पवित्र अग्नि कैसे प्रज्वलित की जाती है, उसका विधि-विधान क्या है, पर मैं उसी विशिष्ट प्रार्थना के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं जो मेरे गुरुदेव ने आपको प्रसन्न करने के लिए पढ़ी थी, कि मेरे देश के निवासी कष्ट में हैं, कृपया उनके कष्ट का निवारण कीजिए। परमात्मा ने फिर से कृपा की, फिर से चमत्कार हुआ और यहूदियों के कष्टों का निवारण हुआ। एक पूरी पीढ़ी बीत गई और उसके बाद जब रब्बी मोशे येहुदा लीब एब्रिलच, जिन्हें सासोव के रब्बी मोशे लीब के नाम से भी जाना जाता है, ने जंगल में जाकर परमात्मा से प्रार्थना की कि न तो मैं पवित्र अग्नि प्रज्वलित करने का तरीका जानता हूं, न ही मुझे वह विशिष्ट प्रार्थना आती है, पर कृपया मेरे देशवासियों का कष्ट हर लीजिए। परमात्मा ने फिर प्रार्थना सुनी, फिर चमत्कार हुआ और एक बार फिर यहूदियों ने सुख की सांस लेना आरंभ किया। इसके भी आधी शताब्दी के बाद रुजिन के दिव्यांग रब्बी इजरायल फ्राइडमैन, जिन्हें इजरायल रुजिन भी कहा जाता है, ने अपनी ह्वीलचेयर से ही परमात्मा से निवेदन किया कि मुझे न तो जंगल के उस स्थान का पता है, न ही पवित्र अग्नि के प्रज्वलन का तरीका पता है और न ही मुझे वह विशिष्ट प्रार्थना आती है, पर मैं इस सत्य का बखान कर रहा हूं कि हे परमात्मा, आप बहुत कृपालु हैं।

कृपया हमारे कष्ट हर लीजिए। और एक बार फिर चमत्कार हुआ, एक बार फिर परमात्मा ने दया की और एक बार फिर यहूदियों को अत्याचारों से छुटकारा मिला। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पूजा में श्रद्धा चाहिए, भक्ति में श्रद्धा चाहिए और उस श्रद्धा में पूरा विश्वास चाहिए। अगर हम ऐसा कर सकें तो फिर परमात्मा की पूजा के लिए किसी विशिष्ट विधि-विधान की आवश्यकता नहीं है। हम सब ने पंद्रहवीं शताब्दी के महान भक्त धन्ना जाट की कहानी सुन ही रखी है जिन्होंने एक पत्थर को शालिग्राम समझकर उनकी पूजा-अर्चना करके भोग लगाने की कोशिश की तो भगवान को प्रकट होकर उनका भोजन स्वीकार करना पड़ा। धन्ना जी को किसी विधि-विधान की जानकारी नहीं थी, उनके पास तो असली शालिग्राम भी नहीं था। उनके पास श्रद्धा थी और अपनी श्रद्धा पर विश्वास था। इसी श्रद्धा और विश्वास ने त्रिलोकीनाथ परमात्मा को विवश किया और उन्हें मानव रूप में पधारकर धन्ना जी के साथ भोजन ग्रहण करना पड़ा। हम ज्ञानी हों, अच्छी बात है, मगर प्रेमी भी हों, मन में अपार श्रद्धा भी हो तो मानो सोने पर सुहागा। हम चाहे सम्पूर्ण जगत का ज्ञान रख लें, पर साथ में इस ब्रह्मांड की हर जड़-चेतन वस्तु और प्राणि मात्र से प्रेम करें तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी और शर्त की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा सा अंतर यह है कि ज्ञानी संसार से मुक्त होना चाहता है, जबकि प्रेमी सारे संसार को परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी सेवा करना चाहता है। एक विद्वान ने कहा है कि ज्ञान में जीव परमात्मा को जानता है और प्रेम में परमात्मा जीव को जानते हैं। ज्ञान पुष्प है और प्रेम श्वास है। प्रेम में जियो, प्रेम ही साधना की पूर्णता है। प्रेम ही ज्ञान का शिखर है, योगी न बनो तो कोई बात नहीं, मगर प्रेमी बन जाओ तो श्रीकृष्ण गोपियों की तरह एक दिन द्वार पर माखन मांगने आ जाएंगे। सच भी यही है कि जब हमारे व्यवहार और हमारी बातचीत में ईमानदारी हो, विनम्रता हो, करुणा हो और प्रेम हो तो हम अध्यात्म को समझने लग गए और परमात्मा के नजदीक हो गए।

जब हमने झूठ बोलना, धोखा देना, फरेब करना, दिखावा करना छोड़ दिया तो हम दिव्यता को पा गए और परमात्मा के नजदीक हो गए। जब हमने अनावश्यक संग्रह का लालच छोड़ दिया और हममें सेवा का भाव आ गया तो हम परमात्मा के नजदीक हो गए। जब हमने परमात्मा पर विश्वास करना आरंभ किया और अपने विश्वास का विश्वास किया, तो हम परमात्मा के नजदीक हो गए। 'सहज संन्यास मिशन' में हम यही सीखते हैं कि सहज जीवन जियें, परमात्मा से प्रेम करें, और इस ब्रह्मांड के हर जड़-चेतन वस्तु और प्राणी को परमात्मा का स्वरूप जानकर प्रेममय हो जाएं तो हम घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी संन्यासी ही हैं। निश्छल प्रेम, हर किसी से प्रेम, बिना कारण, बिना आशा के हर किसी से प्रेम। मानवों से ही नहीं, पशु-पक्षियों और पेड़-पौधों से भी प्रेम, जीवित लोगों से ही नहीं, जीवन रहित मानी जाने वाली चीजों से भी प्रेम, यही सच्ची आध्यात्मिकता है। संत कबीर कहते हैं कि 'खोजी होए, तुरत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूं विश्वास में।' तो आइये, परमात्मा पर विश्वास करें और इस विश्वास पर विश्वास रखें ताकि हमारा जीवन सहज-सरल हो जाए और हम परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। ईश्वर को पाने का रास्ता सर्वनिष्ठ प्रेम ही है।

संपादक की कलम से

आतंकवाद का नया कश्मीर

अब डोडा जिले की बारी है। राजौरी-पुंछ, कठुआ और डोडा सभी जम्मू संभाग के हिस्से हैं। बीते तीन सप्ताह के दौरान तीन आतंकी हमले हो चुके हैं। डोडा आतंकी मुठभेड़ में कैप्टन समेत चार सैनिक 'शहीद' हुए हैं। इससे पहले कठुआ में 'पुलवामा का सारांश' सरीखा हमला किया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। बीते दो साल में 1 कर्नल, 3 कैप्टन, 5 मेजर समेत 10 अफसर कुर्बान करने पड़े हैं। हालांकि 2005 से 2021 तक जम्मू संभाग बिल्कुल शांत रहा। यह सेना प्रमुख से लेकर सत्ताधारी लोगों का मानना और दावा भी है, लेकिन अब जम्मू 'आतंकवाद का नया कश्मीर' बनता जा रहा है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एवं उत्तरी कमान के प्रमुख जनरल रहे दीपेन्द्र सिंह हुड्डा का मानना है कि जम्मू संभाग के इस इलाके में मैदान कम और जंगल ज्यादा, घने हैं। डोडा में जहां आतंकी हमला हुआ, वहां पहाड़ के एक तरफ 200 वर्ग किमी का जंगल है, जबकि हमारा तलाशी अभियान सिर्फ 50 वर्ग किमी में ही चलता रहा है। कश्मीर में जंगल कम और बर्फ के पहाड़ ज्यादा हैं, लिहाजा आतंकियों पर दूर से भी नजर रखी जा सकती है। जम्मू के लिए हमें नई, आक्रामक रणनीति बनानी चाहिए। कश्मीर घाटी में इतने सुरक्षा बल आज भी हैं कि आतंकी हरकत करने के घंटे-दो घंटे में आतंकियों को ढेर किया जा सकता है। जम्मू में सुरक्षा बल अपेक्षाकृत कम हैं। आतंकी उसी का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। जंगल इतने घने हैं कि हेलीकॉप्टर या ड्रोन से आतंकियों के सुराग नहीं लगाए जा सकते। बहरहाल यदि रणनीति बदलनी है, तो वह कब तक बदली जाएगी? अथवा हम शहादतों के आंकड़े गिनते रहेंगे? बेशक हमारे सुरक्षा बलों ने 2023 में 87 आतंकी और 3 जुलाई, 2024 तक 21 आतंकियों को ढेर किया है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? आतंकी तो मरने के लिए या जेहाद की खातिर सीमा पार करके हमारे जम्मू-कश्मीर में घुसते हैं।

उनके साथ मुठभेड़ में या आतंकी हमले में भारत के जो सैनिक 'शहीद' होते हैं, क्या उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? क्या उनकी भरपाई की जा सकती है? एक लंबी, थकाऊ ट्रेनिंग और लाखों रुपए खर्च करके औसतन एक सैनिक तैयार किया जाता है। आखिर शहादत का यह सिलसिला कब तक चलेगा? क्या हमारे सैन्य ऑपरेशन आतंकियों और 'कश्मीर टाइगर्स' सरीखे आतंकी गुट को नेस्तनाबूद करने के मद्देनजर संचालित नहीं किए जा सकते? कठुआ वाला हमला भी इसी आतंकी गुट ने किया था। वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन 'जैश-ए-मुहम्मद' का जम्मू-कश्मीर में एक फर्जी, नकली नाम है। 'कश्मीर टाइगर्स' के आतंकी पाकिस्तान में भर्ती होते हैं, वहीं ट्रेनिंग लेते हैं और 'दिवालिया' पाकिस्तान ही उन्हें पैसा देता है। सवाल है कि ऐसे संगठन को जम्मू-कश्मीर की सरजमीं पर ही चित्त क्यों नहीं किया जा सकता? इन आतंकियों के जो मददगार 'स्थानीय जयचंद' हैं, उन्हें भी ढेर क्यों नहीं किया जा सकता? क्या भारत सरकार ने सैनिकों के हाथ बांध रखे हैं? 2021 से अब तक सेना और पुलिस के 52 जवान आतंकी हमलों में जान गंवा चुके हैं। इस पर संतोष किया जा सकता है कि 54 आतंकी भी ढेर किए गए हैं। इस पर क्या कहेंगे कि 70 से अधिक नागरिक भी मारे गए हैं। कश्मीर घाटी का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान वाली नियंत्रण-रेखा से लगता है, लेकिन डोडा तो नियंत्रण-रेखा के करीब भी नहीं है, फिर वहां तक आतंकियों ने घुसपैठ कैसे की? जम्मू-कश्मीर में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। कश्मीरी अपनी सरकार और प्रतिनिधि चुन सकेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी। उसके मद्देनजर आतंकवाद बढ़ा है। उसे कुचला जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है और डीजीपी आरआर स्वैन को बर्खास्त करने की मांग की है, वह उनकी कुंठा है, क्योंकि वह पाकपरस्त रही हैं। आखिर स्वैन ने क्या कर दिया या क्या कह दिया? उनके सवाल स्वाभाविक हैं। ऐसी सियासत से जम्मू-कश्मीर का भला नहीं होगा।

राय

हिमाचली तर्कों का संघर्ष

बहते दरिया को लावारिस मत समझो, इसकी हर बूंद में हक का जोश भरा है। अपनी खूबियों, प्राकृतिक संपदा, पर्वतीय निर्लिप्तता और राष्ट्रीय योगदान के बावजूद हिमाचल के औचित्यपूर्ण हक पर कुंडलियां मारकर बैठे इंसाफ को जगाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रधानमंत्री से हालिया मुलाकात का लब्बोलुआब यही है कि पहाड़ की दौलत को यूं न रौंदा जाए, यहां भी आत्मसम्मान का दौर मेहनतकश है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आर्थिक संसाधनों की गिरवी फाइल खोली है, वरना एक शांतिप्रिय राज्य के लिए इस तरह की अरदास शोभा नहीं देती, लेकिन हमारे तर्क आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मसला पानी से शुरू होकर राष्ट्रीय संसाधनों की इज्जत में इजाफा करता है। पंजाब पुनर्गठन के बोझ को पीठ पर उठाए हिमाचल का अस्तित्व पूछ रहा है कि फैसले की निगाहों में 'हम आपके हैं कौन।' बीबीएमबी के पास 4200 करोड़ की देनदारी, लीज खत्म होने पर शानन प्रोजेक्ट की वापसी और बिजली पर मुफ्त रॉयल्टी का दायरा पूर्व की परियोजनाओं पर अमल में लाने की ईमानदारी पर हिमाचल की अनदेखी हो रही है। मामले अदालतों में जीत कर भी अगर चीख रहे हैं, तो आगे बढ़ने के रास्ते फिर से खोदने पड़ेंगे। अधिकारों की जंग यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हिमाचल के मांग पत्रों में इनसाफ के तराजू पहले से ही रुके पड़े हैं। राष्ट्र निर्माण के मानदंड पर हिमाचल की वकालत हर केंद्र सरकार से रही है और इसके नतीजों में कुछ खुराक भी मिली है। जिस मुफ्त विद्युत रॉयल्टी का तर्क अब केंद्र से मुखातिब है, उसकी भरपाई में तत्कालीन शांता कुमार सरकार को कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार का आशीर्वाद मिला था, यानी यह फैसला राजनीति से हटकर पहाड़ की वेदना पर मरहम लगाने की नीयत से मिला था। पर्वतीय राज्यों को विशेष आर्थिक दर्जा अब कतरब्यौंत के पैमानों में नजरें चुरा रहा है।

इसी आधार पर स्मार्ट सिटी परियोजनाएं अगर चलतीं, तो यह प्रदेश अपना जायज हक प्राप्त करता। अब कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार का मुद्दा केंद्र के समक्ष है जहां भूमि अधिग्रहण पर पचास : पचास के अनुपात में मोदी सरकार से फंडिंग मांगी जा रही है। हालांकि कायदे और राष्ट्रीय भावना से ऐसी प्रगतिशील योजनाओं की फंडिंग में केंद्र सरकार को नब्बे फीसदी भरपाई करनी चाहिए। जिस प्रदेश को जंगल बना देने की वकालत में आर्थिक अधिकार और आर्थिक विकास की सारी संभावनाएं बंधक बना देने में एक निश्चित प्रणाली विकसित रही हो, वहां सत्तर फीसदी जगह को रोक कर बैठी वन भूमि की राष्ट्रीय भरपाई होनी चाहिए। इसी बरसात में नौ हजार हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त वन तैयार करने की योजना तैयार है। अगर इतनी ही जमीन पर आर्थिक संसाधन विकसित करने में केंद्र मदद करे तो हजारों बेरोजगारों के हाथ में काम आएगा। हम जंगल की आग और पेड़ों के गिरने से हर साल जान-माल का नुकसान झेलते हैं, लेकिन ऐसी कोई परिपाटी नहीं जो इस हानि की जिम्मेदारी ले ले। हम उत्तर भारत की प्रमुख नदियों, बांधों व पेयजल परियोजनाओं में साल भर पानी भरते रहते हैं, लेकिन बाढ़ की स्थिति में केंद्र भूल जाता है कि पहाड़ के किनारे जब टूटते हैं तो कितनी ही छतें और खेत की मिट्टी व उर्वरता बह जाती है। पिछले साल की आपदा इस साल की बरसात में भी रो रही है, तो प्रधानमंत्री को इसलिए भी गौर करना चाहिए कि इस बार भी उनकी एनडीए सरकार के गठन में हिमाचल ने अपने सौ फीसदी सांसद भाजपा को दिए हैं। बेहतर होता हिमाचल के मांगपत्र पर तमाम भाजपा सांसदों के भी हस्ताक्षर होते। अगर हिमाचल में उगते जंगल राष्ट्र की दौलत हैं, तो इस राज्य के ग्रीन चरित्र को परिमार्जित करने के लिए केंद्र को एक मॉडल के तहत वांछित सहयोग करना चाहिए।

कवच-कुंडल की तलाश

लगता है देश में आजकल हर व्यक्ति अपने लिए एक कवच और कुंडल की तलाश कर रहा है। भई, यह कैसा संग्राम है, जिसमें रणबांकुरों को बिना उचित अस्त्र-शस्त्र, बिना किसी कवच-कुंडल के उतार दिया गया? अब बताइए, हमें लड़ाई तो लडऩी है, चाहे अपनी भूख से लड़िए, चाहे अपनी रोजी के लिए लड़िए या फिर कम्बख्त इन बेचेहरा रोगों से लड़िए। प्रतीक्षारत आदमी सोचता है। भई, इलाज का हर प्रयोग क्या हम पर शुरू नहीं किया जा सकता था। जानवरों की बारी बाद में आ जाती। इस देश में शेवरलेट गाड़ी से उतरती मेमसाब की गोद के टॉमी के साथ हमारा क्या मुकाबला? भूखे, प्यासे और बेकार हो गए करोड़ों लोगो, अगर तुम जानवरों से बदतर हो, तो यह तुम्हारा भाग्य। यह भाग्य इतनी सदियों से नहीं बदला, अब क्या बदलेगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी रक्षा स्वयं करो। अपना कवच और कुंडल स्वयं तलाश करो। लगी लगाई नौकरी छूट गई। जेब में जहर खाने के लिए पैसे नहीं। दाना पानी कैसे खरीदेंगे? कहीं से मुफ्त दिलवा दीजिए। अरे यहां मुफ्त तो रोटी-दाल की उम्मीद भी न रखना। इसे राशन कार्ड और मनरेगा वाले ले उड़े। आपको नहीं मिली तो जांच करवाएंगे, कि इन लोगों के कार्ड जाली हैं या प्रामाणिक। साब, यूं ही होता है, आदमी अपना प्रामाणिक प्रमाणपत्र टटोलता रह जाता है और जाली आदमी, सिफारिशी, अपना आदमी या बीच का आदमी होने की दुहाई देकर सब ले उड़ता है। हमने अपने आसपास देखा, बहुत से लोग रियायती राशन की बंद दुकानों पर सिर पटक कर खाली यूं ही जा रहे थे। अब अपना फटा गमछा मुंह पर लपेट रहे थे। सदा ऐसे ही होता है बरखुरदार। राह चलते एक बड़े बूढ़े ने हमारी निराशा देख कर हमें समझाया कि इन कुर्सीधारियों से क्या उम्मीद रखते हो? बेहतर है, अपना कवच-कुंडल खुद ही तलाश लो। शायद तुम्हारे हिस्से के कवच-कुंडल तो इन्होंने अपने बन्धु-बान्धवों में बांट दिए हैं। हमें उनकी बात समझ में आ गई। राशन की इन बंद दुकानों की तरह जिनके जनता द्वार बंद रहते हैं और चोर गलियों में खुलते इनके पिछवाड़े की खिडक़ी सदा खुली रहती है।

हमारे कवच-कुंडल अपने लोगों में बांट देने के लिए। लीजिए अब पूरी राहत सामग्री तो बंट गई और अपने राज्य के भाग्य नियंताओं का बयान है कि जितनी राहत सामग्री आती थी, उसका एक-तिहाई भी नहीं बंटता था, क्योंकि दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं थे। यही कहानी अधबनी सडक़ें, निर्माण के बीच में ठिठके हुए पुल और अजन्मे ही मृत हो गई योजनाएं कहती हैं। इनको लोगों की सुविधा के लिए प्रदान कर देने की घोषणाएं कभी कर दी गई थीं। आपको अपने हिस्से की तलाश करनी है तो अपने उन नेता जी की कीजिए, जो पिछले चुनाव के दिनों में आपके घर, मोहल्ले के स्थायी मेहमान थे। अब कभी नजर नहीं आए। आते भी कैसे? अभी तो अधूरी योजनाओं के पूरे ठेकेदार उन्हें भुगतान दिलवा देने के लिए घेरे हैं। उन्हें वायदा दे रहे हैं, पैसा दिलवाइए मालिक, आपके कवच के लिए कोई बंगला बना देंगे, ताकि अगले चुनाव में इन अंधेरी गलियों की मेहमानी आपको झेलनी न पड़े। लीजिए, आप भी जनाब किन बातों में पड़ गए। देखिए, दुनिया भर में महामारी से लाखों लोग चल बसे। आपको तो पता है, 'जान है तो जहान है।' जान हमारी और जहान भी हमारा। आपको कुछ बचा कर रखना है तो अपने लिए अपना कवच खुद तलाश लीजिए बन्धु, अभी तो बस दिलासा ही भेंट कर सकते हैं। अपनी रक्षा आप कर लीजिए। वैसे भी हमने देश भर के लिए आत्मनिर्भरता का नारा दे रखा है। अब हर बात पर हमारी बाट देखते न रहिए। हम तो अब आपको अगले चुनाव के समय में ही मिलेंगे।

सुरेश सेठ

विचार

प्रदेश में सरकार चलाने की चुनौतियां

हिमाचल सरकार को पर्यटन, हाइड्रो पावर और उद्योगों में निवेश पर और अधिक फोकस करना होगा। सैलानियों का आंकड़ा कम से कम पांच करोड़ सालाना पहुंचने से पर्यटन सेक्टर में उछाल आएगा और गगल हवाई पट्टी के शीघ्र विस्तारीकरण से हिमाचल को पर्यटन क्षेत्र से बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा बरसात के कारण हिमाचल को दस हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। केंद्र को वित्तीय सहायता देनी चाहिए

हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में जीतने के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई थी। पुरानी पेंशन बहाली सहित दस गारंटियों के आश्वासन के बाद सत्तासीन हुई सुक्खू सरकार के लिए पिछले 18 महीने पूरी तरह से चुनौतियों भरे रहे हैं। एक तरफ उनकी सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को लागू करने के वायदे पर खरा उतरी है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे वर्ष 2023 के मध्य में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के मोर्चे पर भी लड़ाई लडनी पड़ी थी। इतना ही नहीं सुक्खू सरकार को सीमित केंद्रीय सहायता और राज्य भाजपा ईकाई द्वारा सरकार को सत्ताच्युत करने के कथित षड्यंत्रों एवं पार्टी के अंदरूनी भितरघात से भी लगातार भिडना पड़ा और जिसकी परिणति गत सप्ताह तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय और पुनः विधानसभा में 40 के आंकड़े पर पहुंचने से हुई मानी जा सकती है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष पिछले डेढ़ वर्ष से सुक्खू सरकार के गिरने के दावे करते आ रहे हैं, लेकिन तमाम तिकड़मबाजियों के बावजूद उनका दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार होता नहीं दिख रहा है। अब चूंकि सुखविंदर सुक्खू सरकार पुनः पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर चुकी है, तो उसके समक्ष सबसे बढ़ी चुनौती राज्य की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की रहेगी।

सरकार के सामने जहां निरंतर घटते राजस्व की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बढ़ते कर्ज और देनदारियों का दबाव भी है। बढ़ती महंगाई के आलम में सरकार के समक्ष कर्मचारियों को पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उनके देय वित्तीय लाभ देने की बाध्यताएं भी हैं। सरकार पर कर्मचारियों एवं पेंशनरों को जल्द एरियर्स सहित डीए देने की मांग भी जोर पकड़ रही है, तो वहीं अपनी दी हुई गारंटियों को पूरा करने की जवाबदेही भी है। हिमाचल प्रदेश शीघ्र ही कर्ज में डूबे एक लाख करोड़ वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल होने वाला है। आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ को लेकर अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी आगे है और 31 मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश पर 94992 करोड़ रुपए के लोन का भार हो जाएगा। इस वित्त वर्ष की लोन लिमिट (दिसंबर 2024 तक) 6200 करोड़ रुपए है। यह लिमिट अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक, यानी नौ माह की है। दिसंबर के बाद आखिरी तिमाही के लिए केंद्र सरकार अलग से लिमिट सेंक्शन करेगी। हिमाचल के पास खुद के आर्थिक संसाधन न के बराबर हैं। हिमाचल में राजस्व के साधनों में ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, शराब की बिक्री ही प्रमुख हैं। कैग की रिपोर्ट में हर बार हिमाचल के लिए चेतावनी होती है कि यदि स्थितियां न सुधरी तो राज्य दिवालिया हो जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष के आंकड़े देखें तो वर्ष 2024-25 में सौ रुपए में से वेतन पर 25 रुपए, पेंशन पर 17 रुपए, ब्याज देने पर 11 रुपए, कर्ज अदायगी पर 9 रुपए, स्वायत्त संस्थानों को ग्रांट पर 10 रुपए खर्च होंगे और विकास के लिए महज 28 रुपए बचते हैं। हिमाचल प्रदेश को खुद के आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए गंभीरता से काम करने की जरूरत है। राजस्व के लिए वाटर सेस लाया गया था, लेकिन वो कानूनी पचड़े में फंसने के कारण अटक गया है। अब पावर सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, तो वहीं बीबीएमबी परियोजनाओं के हिस्से के अलावा शानन विद्युत प्रोजेक्ट में अपना हक लेने के लिए प्रयास भी करने पड़ेंगे। पर्यटन, कृषि, बागवानी पर भी फोकस करने की जरूरत रहेगी।

इस बार वित्तायोग ने यदि हिमाचल पर मेहरबानी नहीं की तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार वेतन व पेंशन सहित देनदारियों के मोर्चे पर गंभीर संकट में फंस सकती है। गत वर्ष सरकार ने राज्य की आर्थिक हालत पर श्वेत पत्र लाने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में कमेटी बनाई थी। समिति ने श्वेत पत्र में बताया कि मौजूदा सरकार को विरासत में 92774 करोड़ की देनदारियां मिली थीं। भाजपा सरकार ने चुनावी साल में 16261 करोड़ उधार लिया, लेकिन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और एरियर्स का भुगतान नहीं किया गया। वित्त आयोग से राज्य में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं में केंद्र सरकार से 30 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की गई है और केंद्र सरकार के पास जमा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लगभग 9000 करोड़ रुपए वापस दिलाए जाने की मांग भी की गई है। वीरभद्र सिंह सरकार के समय सीनियर लीडर विद्या स्टोक्स की अगुवाई में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी बनाई गई थी।

उस कमेटी ने सरकारी खर्च कम करने की सलाह दी थी। इस सुझाव पर सुक्खू सरकार को गंभीरतापूर्वक काम करते हुए अनावश्यक घोषणाओं से बचना होगा और फ्री की स्कीमों पर विराम लगाने की जरूरत है। हिमाचल सरकार को पर्यटन, हाइड्रो पावर और उद्योगों में निवेश पर और अधिक फोकस करना होगा। सैलानियों का आंकड़ा कम से कम पांच करोड़ सालाना पहुंचने से पर्यटन सेक्टर में उछाल आएगा और गगल हवाई पट्टी के शीघ्र विस्तारीकरण से हिमाचल को पर्यटन क्षेत्र से बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा बरसात के कारण हिमाचल को दस हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करके आवश्यक वित्तीय सहायता हिमाचल सरकार को देनी चाहिए। बहरहाल यह कटु सत्य है कि वर्तमान विषम आर्थिक परिस्थितियों में राज्य की सरकार चलाना किसी भी राजनेता के लिए किसी गंभीर चुनौती से कम नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैसे इस चुनौती से पार पाते हैं, यह आने वाला समय ही बताएगा।

अनुज आचार्य

ट्रेन यात्रा के लिए इन नियम और शर्तों का रखना होगा खास ध्यान, एडवांस रिजर्वेशन के लिए ये बातें भी जरूरी

परिवहन विशेष न्यूज

ट्रेन से रोजाना लाखों लोग सफर कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे की ओर से यह खास ध्यान रखा जाता है कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न आए। इसी कड़ी ट्रेन यात्रा से जुड़े नियमों को बनाया गया है। इन नियमों को मानने के साथ कई परेशानियों का समाधान हो जाता है। ट्रेन से सफर करते हैं तो इन नियमों को चेक कर सकते हैं।

नई दिल्ली। ट्रेन से रोजाना लाखों लोग सफर कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे की ओर से यह खास ध्यान रखा जाता है कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न आए। इसी कड़ी ट्रेन यात्रा से जुड़े नियमों को बनाया गया है। इन नियमों को मानने के साथ कई परेशानियों का समाधान हो जाता है। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो रेलवे के इन नियमों की जानकारी आपके काम आ सकती है।

रिजर्वेशन से लेकर सोने के समय को लेकर बने हैं नियम

ट्रेन में रिजर्वेशन से लेकर सोने के समय को लेकर नियम बनाए गए हैं। इस आर्टिकल में ट्रेन यात्रा से जुड़े 6 जनरल नियमों को लेकर ही जानकारी दे रहे हैं-

नियमों के मुताबिक, बर्थ या सीट रिजर्व करने के लिए यह जरूरी है की यात्रा करने वाला व्यक्ति रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस या ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी से ही टिकट बुक करे।

सभी क्लास और ट्रेन के लिए एडवांस रिजर्वेशन तीन महीने पहले यानी 90 दिन पहले तक ही किया जा सकता है।

एक व्यक्ति एक फॉर्म पर अधिकतम छह यात्रियों की ही बुकिंग कर सकता है, बशर्ते सभी यात्री एक ही गंतव्य और एक ही ट्रेन के लिए हों। अगर आगे/वापसी की यात्रा शामिल है, तो एक ही यात्री के लिए 2 या 3 फॉर्म स्वीकार किए जा सकते हैं।

यात्रा टिकट खरीदे बिना आवास रिजर्व नहीं किया जाता है। आवास का रिजर्वेशन प्रोविजनल बेसिस पर भी नहीं होता।

यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्वेशन के साथ नियम है कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सोने का समय रहेगा। वहीं, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के दौरान यात्री जरूरत पड़ने पर डिब्बे में दूसरे लोगों के लिए जगह बना सकते हैं।

रिजर्वेशन से जुड़ी किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए पीएनआर नंबर बताना जरूरी है। यह हर टिकट के ऊपर बायीं ओर प्रिंट होता है।

सोने में आई चमक, वहीं चांदी हुई सस्ती; जाने गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

पिछले सत्र में गोल्ड की कीमत 75700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। लगातार छठे सत्र में बढ़त दर्ज करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 700 रुपये बढ़कर 76400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। विदेशी बाजार में कॉमेक्स सोना 6.90 डॉलर प्रति औंस की बढ़त के साथ 2466.80 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

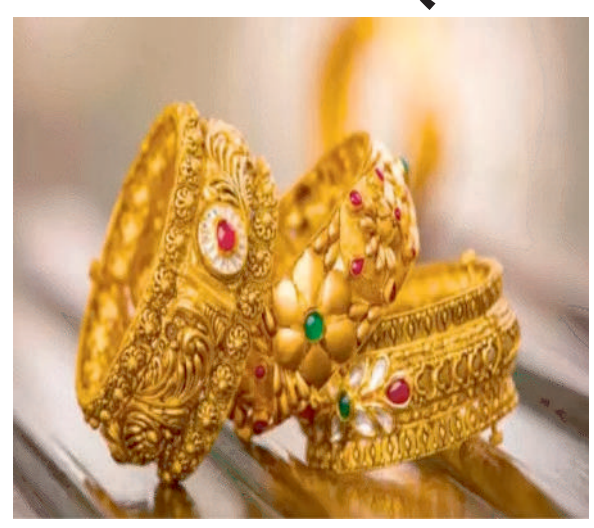

नई दिल्ली। स्थानीय बाजार में गुरुवार को ताजा घरेलू मांग के साथ-साथ रुपये में गिरावट के कारण सोना 700 रुपये बढ़कर 76,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं, चांदी की कीमत पिछले सत्र के 94,400 रुपये प्रति किलोग्राम से 400 रुपये घटकर 94,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

Gold-Silver के लेटेस्ट प्राइस

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, पिछले सत्र में गोल्ड की कीमत 75,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। लगातार छठे सत्र में बढ़त दर्ज करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 700 रुपये बढ़कर 76,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। इस बीच, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 750 रुपये बढ़कर 76,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। हालांकि, चांदी की कीमत पिछले सत्र के 94,400 रुपये प्रति किलोग्राम से 400 रुपये घटकर 94,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

संघ ने कहा कि स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की सतत खरीदारी के कारण सोने की कीमतों में तेजी आई। रुपये में कमजोरी से भी गोल्ड की कीमतें बढ़ी हैं। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की गिरावट के साथ 83.64 (अनंतिम) के अपने सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर बंद हुआ। मुहर्रम के अवसर पर बुधवार को कमोडिटी बाजार बंद रहे।

विदेशी बाजार का हाल

विदेशी बाजार में कॉमेक्स सोना 6.90 डॉलर प्रति औंस की बढ़त के साथ 2,466.80 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं, न्यूयॉर्क में चांदी भी मामूली बढ़त के साथ 30.66 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीद और डॉलर के कमजोर होने के बीच इस सप्ताह की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोने की कीमतें स्थिर रहीं। हालांकि, इस सप्ताह बाजार सहभागियों को 2024 में दो बार दरों में कटौती की उम्मीद है।

अभी भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा फूड प्रोसेसिंग उद्योग, बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में मिल सकता है रोजगार

दर की रफ्तार आठ फीसद से ज्यादा बनाए रखने में मदद कर रहा है, बल्कि युवा वर्ग को रोजगार देने और निर्यात बढ़ाने में भी इसका महत्व बढ़ता जा रहा है।

सरकार के आंकड़े बताते हैं कि देश में जितने पंजीकृत फैक्ट्री रोजगार हैं, उसमें तकरीबन 12.38 फीसद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े हैं। सीधे तौर पर ही इस उद्योग में 19 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं। परोक्ष तौर पर रोजगार के अवसरों की संख्या इससे काफी ज्यादा है। वर्ष 2022-23 में भारत खाद्य व खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात 51 अरब डालर का रहा था। केंद्र सरकार की तरफ से पिछले 20 वर्षों के दौरान इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) और पीएम माइक्रो प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम (PMFME) जैसी स्कीमें लांच की हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में है संभावनाएं

जब दैनिक जागरण की टीम ने उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उद्यमियों से बात की तो तस्वीर का एक दूसरा भी पहलू सामने आया है। अधिकांश उद्यमी यह मानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अभी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन इस उद्योग को आज भी उन्हीं बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है जो दो-ढाई दशक पहले थीं।

मसलन, देश में एयर कंडीशनिंग स्टोरेज सिस्टम का नेटवर्क अभी तक बहुत खास नहीं है। राज्यों में कृषि योग्य जमीन पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक मंजूरी लेना स्थानीय अधिकारियों से अभी भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। कुछ उद्यमी ब्रांडिंग करने, निर्यात करने और नई तकनीक अपनाने में सरकार से अतिरिक्त प्रोत्साहन की मांग कर रहे हैं। भारत निर्मित खाद्य उत्पादों के निर्यात की राह बहुत आसान नहीं है। खास तौर पर कई देशों की सरकारें भारतीय खाद्य उत्पादों के साथ बहुत सकारात्मक रवैया नहीं अपनाते।

इस समस्या का समाधान सरकार के स्तर पर ही किया जा सकता है। यह बात भी सामने आई है कि किसानों और उद्यमियों के बीच अभी बेहतर संपर्क नहीं बन पाया है। उद्यमियों के लिए सीधे किसानों से उनकी उपज खरीदने की प्रक्रिया आसान नहीं है और बिचौलियों की वजह से यह समस्या कुछ ज्यादा ही जटिल हो जाती है। हरिद्वार और फरीदाबाद के कुछ उद्यमियों ने छोटे स्तर पर उद्यम की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन इसका किस तरह से व्यापक विस्तार किया जाए, इसको लेकर उन्हें सरकार से विशेष प्रोत्साहन की उम्मीद है।

टियर-2 शहरों में 94 प्रतिशत तक बढ़े घरों के दाम, लग्जरी होम की बिक्री में हुई इतनी बढ़ोतरी

परिवहन विशेष न्यूज

24 मझोले बाजारों में आवास कीमतों में दोहरे अंकों की वृद्धि देखी गई। वहीं शेष छह में एकल अंक की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई। आगरा में घरों की कीमतें 2019-20 में 3692 रुपये प्रति वर्ग फुट से अधिकतम 94 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 7163 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में अप्रैल-जून 2024 के दौरान 1.56 अरब डालर के सौदे हुए हैं।

नई दिल्ली। लगातार बढ़ रही आवासीय संपत्तियों की मांग की वजह से पिछले चार वर्षों में टॉप-30 टियर-2 शहरों या मझोले बाजारों में घरों की कीमतें 94 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। रियल एस्टेट डेटा विश्लेषक कंपनी प्रापइक्विटी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान परियोजनाओं के औसत पेशकश मूल्य की तुलना 2019-20 की दरों से की है।

क्या कहते हैं आंकड़े?

आंकड़ों के अनुसार, 24 मझोले बाजारों में आवास कीमतों में दोहरे अंकों की वृद्धि देखी गई। वहीं, शेष छह में एकल अंक की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई। टॉप-10 शहरों में आवासीय संपत्ति की कीमतों में 54 प्रतिशत से 94 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

आगरा में घरों की कीमतें 2019-20 में 3,692 रुपये प्रति वर्ग फुट से अधिकतम 94 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 7,163 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं। गोवा में आवास कीमतों में 90 प्रतिशत, लुधियाना में 89 प्रतिशत, इंदौर में 72 प्रतिशत, चंडीगढ़ में 70 प्रतिशत, देहरादून में 68 प्रतिशत, अहमदाबाद में 60 प्रतिशत, भुवनेश्वर में 58 प्रतिशत, मैंगलोर में 57 प्रतिशत तथा तिरुअनंतपुरम में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

टियर-2 शहर अमृतसर, मोहाली, लुधियाना, चंडीगढ़, पानीपत, देहरादून, भिवाड़ी, सोनीपत, जयपुर, आगरा, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, मैंगलोर, मैसूर, कोयंबटूर, कोच्चि, तिरुअनंतपुरम, रायपुर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, नासिक, नागपुर और गोवा हैं।

रियल एस्टेट क्षेत्र में 1.56 अरब डालर के 19 सौदे हुए

भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में अप्रैल-जून, 2024 के दौरान 1.56 अरब डालर के सौदे हुए हैं। रियल एस्टेट परामर्श कंपनी ग्रांट थार्नटन की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा पिछली (जनवरी-मार्च, 2024) तिमाही से लगभग आठ गुना अधिक है। पिछले साल की समान अवधि में सिर्फ 20 करोड़ डालर के सौदे हुए थे।

लग्जरी घरों की बिक्री 27 प्रतिशत बढ़ी

देश के सात प्रमुख शहरों में चालू साल के पहले छह माह (जनवरी-जून) में चार करोड़ रुपये और उससे अधिक कीमत वाले लक्जरी घरों की बिक्री 27 प्रतिशत बढ़कर लगभग 8,500 यूनिट पर पहुंच गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह लगभग 6,700 यूनिट थी।

ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर को नीतिगत स्पष्टता का इंतजार

ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर्स देश का नया बजट जल्दी ही आने वाला है। जिसको लेकर अभी से कयास लगाए जाने लगे हैं। जिसमें से एक ऑनलाइन गेमिंग क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग क्रिप्टोकरेंसी को नीतिगत स्पष्टता लाने की कोशिश करेंगी। आइए जानते हैं इसके बारे में।

नई दिल्ली। क्या वित्त मंत्री आगामी बजट में प्रौद्योगिकी आधारित नए लेकिन विवादित उद्योग सेक्टर जैसे ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार नीतिगत स्पष्टता लाने की कोशिश करेंगी। पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह से इस बारे में सरकार के भीतर विभिन्न मंत्रालयों के भीतर इस बार में विमर्श चल रहा है, उससे इस बात का संकेत मिलता है कि कुछ बातें हो सकती हैं।

पीएम मोदी ने ऑनलाइन गेमर्स के साथ की थी मुलाकात

जानकार बताते हैं कि जनवरी से मई, 2024 के बीच नये प्रौद्योगिकी आधारित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले वित्तीय लेन-देन की निगरानी को लेकर वित्त मंत्रालय और RBI के बीच भी विमर्श का कई दौर हो चुका है। अप्रैल, 2024 में पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी ऑनलाइन गेमर्स के साथ एक मुलाकात में यह संकेत दिया था कि सरकार की मंशा ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में बहुत सारे कायदे-कानून लाने की नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में CII, फिक्की जैसे उद्योग चैंबरों ने भी उक्त दोनों सेक्टरों को लेकर स्पष्ट नीति लाने की सिफारिश की है। जबकि बजट पूर्व बैठक में कुछ अर्थविदों ने युवाओं में रोजगार सृजन के उद्देश्य से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही थी।

क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन गेमिंग पर लिया जा रहा टैक्स

दैनिक जागरण ने सरकार की उक्त तैयारियों के मद्देनजर क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के प्रतिनिधियों से बात की और इनका जोर मुख्य तौर पर नीतिगत स्पष्टता को लेकर ही है। अभी सरकार की तरफ से इन दोनों उद्योगों से टैक्स लिया जा रहा है लेकिन इन क्षेत्रों को कोई नीतिगत समर्थन नहीं है। इनका यह भी कहना है कि अगर सरकार को नियामक एजेंसी बना कर हमारे उद्योग की निगरानी करनी हो, तो वह भी स्वागतयोग्य है।

भारत में करीब 30 करोड़ लोग खेलते हैं ऑनलाइन गेम

स्किल ऑनलाइन गेम्स इंस्टीट्यूट (सोगी) के प्रेसिडेंट अमृत किरण सिंह का कहना है कि, "सरकार अगर दीर्घकालिक नीति के तहत टैक्स लगाये तो वह पूरी देश की इकोनमी के लिए फायदेमंद होगा। अगस्त, 2023 में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर GST की दर 18 फीसद से बढ़ा कर 28 फीसद कर दिया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय गेमिंग कंपनियां (प्रमुखतः चीन, साइप्रस, तुर्की की) भारतीय ऑनलाइन गेमर्स को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। भारत में तकरीबन 30 करोड़ लोग अभी ऑनलाइन गेम में है जिनकी संख्या जल्द ही 50 करोड़ हो जाएगी। विदेशी गेमिंग कंपनियों पर GST का बोझ नहीं है क्योंकि वह विदेशी जमीन से अपनी सेवा दे रही हैं। वह किफायती दरों पर अपनी सेवा दे रही हैं और इसका खुलेआम प्रचार भी वह कर रही हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार को पहले पूरे उद्योग के कारोबार व देश की इकोनमी व रोजगार में इसके योगदान व संभावनाओं पर एक व्यापक अध्ययन करवा लेना चाहिए और उसके बाद ही फैसला करना चाहिए।

क्रिप्टो लेनदेन के लिए हो एक निकाय

WazirX के वाइसप्रेसिडेंट राजागोपाल मेनन का कहना है कि बजट में अगर क्रिप्टो लेनदेन को लेकर एक विशेष नियामक निकाय की स्थापना की घोषणा हो जाए तो वह इस सेक्टर में ना सिर्फ पारदर्शिता के सवाल का उत्तर होगा बल्कि निवेशकों की सुरक्षा को लेकर जताई जाने वाली आशंकाओं को भी काफी कम कर सकता है। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की तरह इनका भी कहना है कि ज्यादा टैक्स लगाने से भारत की VDA कंपनियों ने अब विदेश से संचालित एक्सचेंजों का रूख कर लिया है। इसका असर सरकार के राजस्व पर भी हो रहा है। इनका कहना है कि एक मजबूत नियामक फ्रेमवर्क स्थापित करके सेबी या RBI के तहत काम करने से क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल एसेट्स सेक्टर में जोखिम कम किया जा सकता है।

कुशल श्रमिकों की कमी और लॉजिस्टिक सुविधा के अभाव से उत्तर भारत में कम निवेश

परिवहन विशेष न्यूज

तमिलनाडु में आज भारत में सबसे अधिक 39600 यूनिट हैं और यह राज्य दुनिया के 10 ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक बन गया है। हालांकि मोबाइल फोन व उनके पा र्ट्स निर्माण में उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी बड़ा निवेश हुआ है लेकिन दक्षिण के राज्यों की तरह ये नए सेक्टर के निवेशकों को बहुत आकर्षित नहीं कर पा रहा है।

नई दिल्ली। पूरे देश के विकास के लिए समान रूप से राज्यों का विकास जरूरी है। पर निवेश का मामला आते ही दक्षिण और उत्तर की खाई इतनी गहरी दिखती है कि समान विकास फिलहाल संभव नहीं दिखता। पिछले दो-तीन सालों में सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु में लगी है और इसके पीछे की वजह है वहां की सरकार उद्यमियों को बहुत ही कम समय में यूनिट लगाने की तमाम औपचारिकताएं पूरी करके दे देती है।

मेक इन इंडिया प्रोग्राम व प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से मिला बढ़ावा

तमिलनाडु में आज भारत में सबसे अधिक 39,600 यूनिट हैं और यह राज्य दुनिया के 10 ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक बन गया है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम व प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम की घोषणा का सबसे अधिक लाभ तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण के राज्यों के साथ गुजरात व महाराष्ट्र को ही मिला है।

इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, सेमिकंडक्टर, केमिकल्स जैसे नए सेक्टर में होने वाले निवेश में इन राज्यों की अधिक हिस्सेदारी दिख रही है। जबकि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारत के राज्य इंजीनियरिंग उत्पाद, छोटी मशीनरी, गारमेंट, ऑटो कंपोनेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, साइकिल निर्माण जैसे पारंपरिक सेक्टर में उलझे रह गए।

हालांकि मोबाइल फोन व उनके पार्ट्स निर्माण में उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी बड़ा निवेश हुआ है और हरियाणा में भी पैसेंजर कार, ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल का भारी निर्माण होता है, लेकिन दक्षिण के राज्यों की तरह ये दोनों राज्य भी नए सेक्टर के निवेशकों को बहुत आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं।

निवेश में भी बढ़ोतरी

औद्योगिक जगत के जानकारों का कहना है कि दक्षिण के राज्य के साथ महाराष्ट्र व गुजरात में इसलिए अधिक नए निवेश आ रहे हैं, क्योंकि इन जगहों पर उत्तर भारत के मुकाबले काफी अधिक संख्या में कुशल श्रमिक उपलब्ध है। इन राज्यों की नीति उद्यमी और निवेश के अनुकूल है।

पोर्ट के समीप होने का अलग फायदा है। लॉजिस्टिक लागत कम है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में इंजीनियरिंग और टेक्निकल कुशलता का माहौल पहले से रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य दक्षिण के इन राज्यों के समीप है, इसलिए यहां भी कुशल श्रमिकों का इको सिस्टम तैयार हो गया।

एपल मोबाइल फोन का प्लांट तमिलनाडु में लगा तो देश में पहली सेमिकंडक्टर निर्माण की यूनिट अमेरिकन कंपनी माइक्रोन गुजरात के सानंद में लगा रही है। इसकी एक मुख्य वजह है कि गुजरात सरकार माइक्रोन को आर्थिक सहायता के साथ अन्य सभी सुविधाएं तय समय में मुहैया करा रही है। सेमिकंडक्टर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की पूरी चेन गुजरात में उपलब्ध है। इससे भी माइक्रोन ने यूनिट लगाने के लिए गुजरात का चयन किया।

इस मामले में तमिलनाडु नंबर-1

पंजाब के उद्यमी एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के चेयरमैन अश्विनी कुमार कहते हैं पंजाब या उत्तर भारत के अन्य राज्यों में दक्षिण के राज्यों की सरकार की तरह उद्योग को प्रोत्साहित करने की नीति नहीं है। राज्य सरकार की तैयारी काफी मायने रखती है।

गुरुग्राम-फरीदाबाद टोल पर जनता का आक्रोश

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम-फरीदाबाद टोल प्लाजा को लेकर जनता का गुस्सा चरम पर है। यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यह टोल रोड है या किरायेदारी ? जनता तत्काल राहत की मांग कर रही है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं:

1.बड़े और छोटे वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश 7-11 बजे सुबह और 5-11 बजे शाम को बंद किया जाए।

2.पीक आवर्स (8-10 बजे सुबह और 6-9 बजे शाम) के दौरान टोल छूट दी जाए।

3.वाणिज्यिक वाहनों का सूरज कुंड से मानव रचना, पाली चौक, मांगर चौक और घाटा की ओर प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।

4. एसपीआर घाटा से मांगर और फरीदाबाद क्रॉसिंग की ओर वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।

5. मानव रचना, पाली चौक, मांगर, बलियास, सोसाइटी कट और घाटा टर्न पर ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जाए या कोई बेहतर समाधान निकाला जाए।

6. टोल प्लाजा से पार्क किए गए वाहनों को हटाया जाए।

7. लैंडफिल साइट से लोडिंग केवल रात में प्रतिबंधित की जाए।

वैकल्पिक रोड की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जैसे कि टोल घाटा की ओर एसपीआर और वटिका चौक की ओर बाईपास रोड, जिसमें फरीदाबाद-गुरुग्राम मेट्रो लाइन भी शामिल हो।

सोशल मीडिया पर change.org पर शुरू की गई याचिका पर 2-3 दिनों में 500 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिससे गुरुग्राम-फरीदाबाद टोल के विरोध में आवाज उठाई गई है।

रवि मनचंदा का सुझाव: "टोल हटाओ, लूट की अनुमति नहीं"

गुरुग्राम-फरीदाबाद टोल प्लाजा पर जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रवि मनचंदा ने इस संदर्भ में सुझाव दिया है: "टोल हटाओ, लूट की अनुमति नहीं।" टोल प्लाजा पर रोजाना हजारों लीटर ईंधन का अपव्यय होता है, साथ ही यात्रियों का कीमती समय भी बर्बाद हो रहा है।

यह स्थिति न केवल आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक है, बल्कि पर्यावरण पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। वाहन चालकों को रोजाना ट्रैफिक जाम और टोल प्लाजा पर लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका समय और ईंधन दोनों ही बर्बाद होते हैं।

जनता की मांग है कि इस टोल प्लाजा को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि यह असुविधा खत्म हो सके और यात्रियों को राहत मिल सके।

शिक्षा से ही समाज का विकास संभव: डवाराराम पंवार

भामाशाह डवाराराम गेनाराम पंवार ने उदयपुर छात्रावास में एक कमरे की घोषणा

बेंगलूरू: सोजत सिटी तहसील के गांव चंडावल के निवासी शिक्षा प्रेमी भामाशाह डवाराराम गेनाराम पंवार ने हाल बेंगलुरू चिकपेट में स्थित रचना फैशन, रचना फैब्रिक्स के प्रमुख ने सीरवी छात्रावास उदयपुर हेतु एक कमरे की स्वैच्छिक घोषणा की। भामाशाह डवाराराम पंवार ने बताया कि बड़े शहरों में अपने विद्यार्थियों के रहने खाने की सुविधा करना बहुत जरूरी है। छात्रावास पढ़ने का अच्छा माहौल देता है साथ ही छात्रावास सहपाठियों के साथ बंधन विकसित करने का मौका प्रदान करता है। डवाराराम पंवार की छात्र हित शिक्षा व सम्रग सामाजिक उत्थान की भाशना के लिए उदयपुर संस्थान की ओर से आभार जताया। भामाशाह डवाराराम पंवार ने कहा कि समाज के प्रत्येक वक्ति की इस सामाजिक संस्था में भागीदारी होनी चाहिए।

श्री बाबाधाम पर गुरू पूर्णिमा पर्व पर रक्तदान व वृक्षारोपण

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा, भीलवाड़ा। श्री बाबा धाम पर रक्तदान व वृक्षारोपण में श्री बाबाधाम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल के सानिध्य में तैयारियों को लेकर श्री बाबाधाम के सभी सदस्य व सेवादारों को मिटिंग में बुलाया गया। तैयारियों में मौसम को देखते हुए विशेष व्यवस्था की जायेगी।

''न चढ़ता है पैसा, न चढ़ता है दान - ऐसा है श्री बाबाधाम
असहाय, बेसहारा लोगों के लिये - यहां होता है रक्तदान''

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविवार 21.07.2024 रविवार को रक्तदान किया जायेगा। भक्तों ने रक्तदान के लिये अपने-अपने नाम लिखवाने शुरू कर दिये है। रक्तदान महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों व स्टॉफ के सहयोग से होगा। ''हरियालो राजस्थान अभियान'' के तहत ''एक पेड़ माँ के नाम'' पौधारोपण कर पेड़ बनने तक का सुरक्षा व देखभाल का संकल्प दिलाया जायेगा। वृक्षारोपण भी रविवार को 21.07.2024 को ही रखा गया है। रक्तदान के लिये जो भी मां के दरबार में रक्तदान करना चाहे वे भक्तजन सादर आमंत्रित है। मीटिंग में कहा गया कि रक्तदान जो भी मां के दरबार में आकर करना चाहे वे अपना नाम लिखा देवें। रक्तदान व वृक्षारोपण के लिये अन्य बिन्दुओं पर भी विस्तृत चर्चा की गयी और आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गयी।

जन-सुनवाई में प्राप्त सभी आवेदनों पर करें शत-प्रतिशत निराकरण – ज़िला कलेक्टर

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा। प्रत्येक तीसरे गुरुवार को आयोजित होने वाले जन सुनवाई में आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याओं, मांगों और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किये। ज़िला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने जन-सुनवाई में आम जनता की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को तुरंत निर्देश जारी किए।

उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि जन-सुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से निराकृत कर उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पहुंचाना है। अतः सभी अधिकारी जन-सुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर शीघ्रता से कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जनसुनवाई में कुल 35 प्रतिवाद प्राप्त हुए जिसमें से 2 परिवादों का मौक़े पर ही निस्तारण किया गया। जनसुनवाई में प्रमुख रूप से अतिक्रमण, रास्ते के प्रकरण, पानी भराव की समस्या, गंदगी, जल निकासी, पानी का कनेक्शन, राशन कार्ड चालू करवाने, तथा पुलिस संबंधी प्रकरण प्राप्त हुए जिनको जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर त्वरित तथा संतुष्टि पूर्ण समाधान के लिए निर्देशित किया।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधिक्षक राजेश कांवत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनील पुनिया, नगर परिषद आयुक्त राम किशोर सहित जिला स्तरीय अधिकारी तथा सभी उपखंड से उपखंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।

प्रतिदिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं व आमजन की जनसुनवाई कर रहे है भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाडा। प्रतिदिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं व आमजन की जनसुनवाई कर रहे है भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल।। सांसद प्रवक्ता विनोद झुरानी ने बताया कि सांसद अग्रवाल प्रतिदिन जनसुनवाई के माध्यम से भीलवाड़ा वासियों को राहत प्रदान कर रहे है।। सांसद महोदय रोजाना 6 घण्टे भाजपा जिला कार्यालय पर आमजन की जनसुनवाई के लिए उपलब्ध रहते है।।। हर कार्यकर्ता व आमजन की समस्या के त्वरित समाधान के लिए सांसद महोदय हर सम्भव प्रयास करते है ।। भीलवाड़ा जिले की आठो विधानसभा क्षेत्र से जनता व कार्यकर्ता अपनी विभिन्न विभागों से सम्बंधित समस्याओं को लेकर पहुच रहे है । सांसद अग्रवाल सभी को समान द्रष्टिकोण से देखते हुए त्वरित समाधान करते है

फिल्म उद्योग में करियर विकल्प : विजय गर्ग

फ़िल्में न केवल मनोरंजन और सूचना का बल्कि संचार का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र, प्रचार फिल्में, टीवी विज्ञापन, संगीत वीडियो आदि शामिल हैं। फिल्म उद्योग पहले से कहीं अधिक बड़ा और विविध है। परिणामस्वरूप, फिल्म निर्माण में करियर रचनात्मक विचारकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है। भारत फ़िल्मों का सबसे बड़ा निर्माता है। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार अकेले बॉलीवुड का मूल्य 2.28 बिलियन डॉलर से अधिक है, जिसमें पिछले वर्ष 11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है। इस तरह की वृद्धि और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में फिल्मों की बढ़ती मांग के साथ, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित फिल्म निर्माताओं की मांग भी बढ़ गई है। फिल्म निर्माण की तकनीक एक टीम वर्क है जिसमें विभिन्न कुशल व्यक्तियों के घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होती है। फिल्म निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई पहलू शामिल होते हैं जैसे कहानी, निर्देशन, पटकथा, छायांकन, अभिनेताओं का चयन, बजट और शूटिंग के लिए स्थान तय करना आदि। फिल्म उद्योग में व्यवसायों की इन श्रृंखलाओं में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से कड़ी मेहनत शामिल होती है। , लंबे समय तक, अक्सर असुविधाजनक स्थानों पर। यदि किसी के पास कलात्मक और तकनीकी कौशल है और साथ ही वह विचारों को व्यक्त करने में सक्षम है, तो यह आपके लिए सही क्षेत्र है। फिल्म उद्योग में करियर विकल्प इस इंडस्ट्री में करियर के लिए व्यक्ति को मूल रूप से रचनात्मक होना चाहिए और उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। फिल्म निर्माण क्षेत्र में करियर के कई रास्ते हैं, यह आपकी पसंद और रुचि पर निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फिल्म उद्योग में कुछ करियर निम्नलिखित हैं। निर्माता: एक निर्माता का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि बाकी सभी लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं। वह कहानी चुनता है, संसाधनों का प्रबंधन करता है, निर्देशक सहित कलाकारों और चालक दल की नियुक्ति करता है, स्थान चुनता है, कानूनी मुद्दों का प्रबंधन करता है आदि। फिल्म के निर्माण और निर्माण के सभी पहलुओं, जैसे कि अवधारणा और लेखन का ध्यान रखना निर्माता की जिम्मेदारी है। कहानी का विवरण, फ़ंडिंग का अधिग्रहण और खुदरा रिलीज़ के लिए उपयोग की जाने वाली कलाकृति। जबकि ऐसे कई अन्य पेशेवर हैं जो निर्देशक, छायाकार और संपादक जैसे फिल्म निर्माताओं की सहायता करते हैं। यह फिल्म निर्माता है जो यह सुनिश्चित करता है कि फिल्म निर्माण प्रक्रिया के सभी चरणों के दौरान सभी उत्पादन घटक एक साथ काम कर रहे हैं। अक्सर यात्रा की आवश्यकता होती है और निर्माता अक्सर लंबे समय तक और कभी-कभी अप्रिय मौसम की स्थिति में काम करते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से संचार, नेतृत्व, प्रबंधन, व्यवसाय और रचनात्मकता जैसे प्रमुख कौशल की आवश्यकता होती है। किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ललित कला, अभिनय, लेखन, पत्रकारिता, कला प्रबंधन या तुलनीय अनुशासन में स्नातक या स्नातकोत्तर सहायक हो सकता है। एक फिल्म/टीवी निर्माता का औसत वेतन 10,00,000 रुपये सालाना है। निर्देशक: एक फिल्म निर्देशक फिल्म निर्माण के रचनात्मक पहलुओं के लिए जिम्मेदार मुख्य व्यक्ति होता है। निर्देशक निर्माता का दाहिना हाथ होता है। यह वह निर्देशक है जिसके साथ ज्यादातर लोगों को काम करना होगा। कोरियोग्राफी, पोशाक, संगीत और क्रू सभी उन पर निर्भर हैं। फिल्म का स्वरूप बनाते समय, फिल्म निर्देशक स्क्रिप्ट में बदलाव कर सकते हैं, फिल्म के स्थान निर्धारित कर सकते हैं, पोशाक डिजाइन को अंतिम रूप दे सकते हैं, विशेष प्रभावों को मंजूरी दे सकते हैं और अभिनेताओं को कोचिंग प्रदान कर सकते हैं। नौकरियां तनावपूर्ण हो सकती हैं, अक्सर समय सीमा के तहत काम करना। विभिन्न मौसम स्थितियों में फिल्मांकन और निर्देशन भी इस पेशे में आम है। एक कुंवारापत्रकारिता, फिल्म, संचार, अभिनय, कला प्रबंधन या किसी प्रासंगिक अनुशासन में डिग्री की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, एक निदेशक में संचार, नेतृत्व, प्रबंधन, व्यवसाय और रचनात्मकता जैसे प्रमुख कौशल मौजूद होने चाहिए। एक निदेशक का औसत वार्षिक वेतन लगभग 8,00,000 रुपये है। संपादक: चूंकि फिल्में लंबी और उलझी हुई तरीके से बनाई जाती हैं, इसलिए संपादक का कर्तव्य है कि वह हर चीज को एक क्रम में रखे। उन्हें अपने दृष्टिकोण को सच रखने के लिए निर्देशक और निर्माता के साथ बहुत करीब से काम करना पड़ता है। एक वीडियो और फिल्म संपादक का काम वीडियो का एक परिष्कृत टुकड़ा तैयार करने के लिए वीडियोटेप लेना है। एक वीडियो एडिटर को किसी भी पोस्ट-प्रोडक्शन प्रक्रिया की रीढ़ माना जाता है। एक वीडियो संपादक की मुख्य जिम्मेदारी केबल और प्रसारण दृश्य मीडिया उद्योगों के लिए साउंडट्रैक, फिल्म और वीडियो जैसे किसी भी दृश्य मीडिया-रूप को संपादित करना है। वह चुनता है कि क्या पुनः शूट किया जाना चाहिए और क्या काटा जाना चाहिए। उसे विशेष प्रभावों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए और साउंडट्रैक को सिंक्रनाइज़ करना चाहिए। इस पेशे में प्रवेश के लिए किसी औपचारिक शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। सभी को डिजिटल वीडियो/फिल्म संपादन में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम में प्रशिक्षण और दृश्य मीडिया के संपादन में रुचि की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर, संपादकों के पास अक्सर एनीमेशन या मीडिया कला में स्नातक या मास्टर डिग्री होती है। संपादक का औसत वार्षिक वेतन लगभग 6,00,000 रुपये है। पटकथा लेखक: पटकथा लेखन कहानी बनाने, पात्रों को विकसित करने और उसी कहानी में संवाद प्रदान करने की कला है। पटकथा लेखक फिल्मों की पटकथा के लेखक होते हैं। वे फिल्म स्क्रिप्ट के संवाद, पात्र और कहानी बनाते हैं। पटकथा लेखक अक्सर फिल्म निर्माण में सबसे आवश्यक व्यक्ति होता है क्योंकि कोई भी फिल्म बिना किसी स्क्रिप्ट के शुरू नहीं हो सकती है। पटकथा लेखक फिल्म की मूल संरचना बनाते हैं और सामान्य आधार प्रदान करते हैं, जिसे बाद में कहानी

जनरेटेड एनीमेशन में काम करते हैं। हालाँकि इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए शैक्षिक आवश्यकताएँ अलग-अलग हो सकती हैं, और कुछ मामलों में, औपचारिक शिक्षा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं हो सकती है, फिल्म एनिमेटरों के पास आमतौर पर ललित कला, कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनीमेशन या इसी तरह के क्षेत्र में एसोसिएट या स्नातक की डिग्री होती है। ए का वार्षिक औसत वेतनफिल्म इंडस्ट्री में एनिमेटर की सैलरी करीब 4,50,000 रुपये है। सिनेमैटोग्राफर: सिनेमैटोग्राफर को फिल्मों को अपनी अनूठी सौंदर्य शैली देने वाले निर्देशकों के साथ-साथ फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में भी जाना जाता है। वे कैमरा क्रू और लाइटिंग क्रू के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। वे स्क्रीन पर आकर्षक छवियां बनाने के लिए तकनीकी उपकरणों के चयन और अंततः फिल्म पर रखकर कल्पना और विस्तृत किया जाता है। बनने के लिए पटकथा लेखन में स्नातक की डिग्री आवश्यक है। एक पटकथा लेखक का औसत वार्षिक वेतन लगभग 7,00,000 रुपये है, बाकी फिल्म के बजट पर निर्भर करता है।

अभिनेता/अभिनेत्री: अभिनेता कहानियों में पात्रों को उनकी आवाज़, रूप, शरीर और हावभाव का उपयोग करके चित्रित करते हैं। एक अभिनेता के रूप में काम करते समय, वे मनोरंजन और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदर्शन करते हैं। अभिनेता मुख्य पात्र या सहायक भूमिकाएँ निभा सकते हैं। अभिनेता चरित्र के बारे में जानने और बोलने वाले हिस्सों को याद करने के लिए स्क्रिप्ट का अध्ययन करता है। अभिनेता निर्देशक के अधीन काम करते हैं जो उन्हें पात्रों को चित्रित करने की सलाह देता है। चरित्र को जीवंत बनाने के लिए, अभिनेता अपनी आवाज़, बोली, चेहरे के भाव और अन्य लक्षण बदलते हैं। अभिनेता की आय पूरी तरह से फिल्म उद्योग में अभिनेता की प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। एनिमेटर: फिल्म एनिमेटर कई छवियों का निर्माण करता है, जिन्हें फ्रेम भी कहा जाता है, जिन्हें जब एक साथ अनुक्रमित किया जाता है तो तेजी से गति का भ्रम पैदा होता है जिसे एनीमेशन कहा जाता है। छवियों को विभिन्न माध्यमों जैसे डिजिटल या हाथ से बनाए गए चित्र, मॉडल या कठपुतली का उपयोग करके बनाया जा सकता है। फिल्म के माध्यम के लिए, एनिमेटर अक्सर कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइन प्रोग्राम का उपयोग करते हैं और 2डी एनीमेशन, 3डी मॉडल-मेकिंग एनीमेशन, स्टॉप फ्रेम या कंप्यूटर-और हेरफेर की भी निगरानी करते हैं। वे नाटकीय प्रभाव पैदा करने और दर्शकों से विभिन्न भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए विभिन्न लेंसों, फिल्टरों, प्रकाश तकनीकों और कैमरा गतिविधियों के उपयोग के बारे में बड़े निर्णय लेते हैं। वे पहलू अनुपात, डिजिटल प्रभाव और छवि कंट्रास्ट और फ्रेम दर के बारे में निर्णय लेने के लिए भी जिम्मेदार हैं। सिनेमैटोग्राफर बनने के लिए डिजिटल कैमरा और कंप्यूटर कौशल, कलात्मक क्षमता या समकक्ष में स्नातक की डिग्री आवश्यक है। जैसे-जैसे सिनेमैटोग्राफर अधिक अनुभवी होता जाता है, उसका वेतन प्रति वर्ष 6,00,000 रुपये तक बढ़ जाता है। कैमरामैन: एक कैमरामैन पूर्वनिर्धारित स्क्रिप्ट के अनुसार या घटना सामने आने पर कार्रवाई को कैप्चर करने के लिए जिम्मेदार होता है। रोबोटिक्स और डिजिटल उपकरणों ने इस काम को शारीरिक रूप से कम कठिन बना दिया है, लेकिन एक कैमरामैन को किसी दूरस्थ स्थान पर शूटिंग करते समय प्रतिकूल मौसम या खतरनाक परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह सिनेमैटोग्राफर का दाहिना हाथ है; उच्च तकनीकी दक्षता और कैमरों का गहन ज्ञान होना चाहिए। कैमरामैन बनने के लिए आपको ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म, पत्रकारिता, फोटोग्राफी या फोटो जर्नलिज्म में स्नातक की डिग्री हासिल करनी होगी। एक कैमरामैन का औसत वेतन 3,20,000 रुपये प्रति वर्ष है। प्रकाश तकनीशियन/ऑपरेटर: प्रकाश तकनीशियन प्रकाश बोर्ड को संचालित करके प्रकाश और दृश्य को नियंत्रित करता है। वह रोशनी में हेराफेरी के लिए भी जिम्मेदार है; रोशनी लटकाना, प्रकाश उपकरणों को उतारना और हिलाना, और यह सुनिश्चित करना कि सभी उपकरण पूरी तरह कार्यात्मक हैं। दिन को रात में बदलना, या सिर्फ रंग बदलने से मूड बदलना; इस कार्य के लिए उच्च तकनीकी कौशल और अनुभव की आवश्यकता है। आप इलेक्ट्रीशियन के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं और उत्पादन प्रकाश व्यवस्था में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आप स्टेज इलेक्ट्रिक्स और लाइटिंग डिज़ाइन जैसे कौशल सीखने के लिए कॉलेज कोर्स भी कर सकते हैं। इस उद्योग में एक लाइट ऑपरेटर का औसत वार्षिक वेतन लगभग 3,50,000 रुपये है। ध्वनि तकनीशियन: ध्वनि तकनीशियन उपकरण ध्वनि रिकॉर्डिंग की स्थापना, रखरखाव और संचालन करता है। आम तौर पर, ध्वनि तकनीशियन जो चीजों के उत्पादन पक्ष पर काम करते हैं, वे शूटिंग के लिए सभी ध्वनि उपकरणों की जांच और तैयारी करने, सेट पर अवांछित ध्वनियों को कम करने के लिए अतिरिक्त व्यावहारिक कार्य करने, किसी विशेष स्टूडियो या स्थान की ध्वनिकी का मूल्यांकन करने और रिकॉर्डिंग की स्थिति निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उपकरण सही समय पर सही जगह पर हों। इसके अलावा, वे फिल्मांकन के दौरान ध्वनि के स्तर में बदलाव करेंगे और ऑडियो संकेतों की निगरानी करेंगे। टीवी शो और फिल्मों में उपयोग किए जाने वाले संवाद, संगीत और अन्य विभिन्न ध्वनियाँ स्पष्ट, स्पष्ट और सशक्त होनी चाहिए। नतीजतन, दर्शकों को संतोषजनक बहु-संवेदी अनुभव प्रदान करने के लिए ध्वनि तकनीशियनों का व्यावहारिक और तकनीकी कौशल बिल्कुल आवश्यक है। एक पेशेवर ध्वनि तकनीशियन बनने के लिए ध्वनि इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी या रिकॉर्डिंग कला में स्नातक की डिग्री आवश्यक है। एक साउंड इंजीनियर का औसत वेतन 3,50,000 रुपये सालाना है। फिल्म उद्योग के तीन पी याद रखें: भावुक, लगातार और धैर्यवान बने रहें और आप मनोरंजन उद्योग में सफल होने की संभावनाओं को नाटकीय रूप से बढ़ा देंगे। तो, ये कुछ लोकप्रिय करियर हैं फिल्म इंडस्ट्री जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**